आवेश शांत
होने पर भी
जो काम
किया जाता है वही
फलदायी होता है।
-महात्मा गांधी-

दैनिक
लोक जीवन
www.lokjeewan.com
जयपुर एवं भीलवाड़ा से प्रकाशित राज्य स्तरीय समाचार पत्र
संस्थापक - स्व. डॉ. शिवकुमार जी त्रिवेदी

लोक जीवन में विज्ञापन
के लिए सम्पर्क करें:-
- : जयपुर : -
0141-4038281
- : भीलवाड़ा : -
8306792625

वर्ष- 19 | अंक- 202 | जयपुर. शनिवार . | 21 नवम्बर , 2026 | RNI No. RAJHIN/2008/26744 | मूल्य 1 रूपया | पृष्ठ - 4

न्यूज इनबॉक्स

भारत-नेपाल मैत्री को मिलेगी रेल कनेक्टिविटी की नई सौगात

जयनगर (एजेंसी)। नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के लोग 23 नवम्बर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह नई दिल्ली से संयुक्त रूप से जनकपुर-अयोध्या ट्रेन सेवा का उद्घाटन करेंगे। दोनों नेता ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर राय ने शुक्रवार को बताया कि प्रधानमंत्री बालेन शाह 22 नवम्बर को नेपाल एयरलाइन्स से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। उनके साथ वित्त मंत्री स्वर्णिम बागले, भौतिक पूर्वाधार मंत्री सुनील लमशार, प्रधानमंत्री के सलाहकार कुमार बेन और राजनीतिक सलाहकार आसिन साह होंगे। भारत की आधिकारिक यात्रा पर प्रधानमंत्री के साथ करीब 34 सदस्यीय टीम होगी। जानकारी के अनुसार, बालेन शाह के साथ नेपाल के 52 व्यापारियों का दल और करीब एक दर्जन मीडियाकर्मी भी नई दिल्ली जाएंगे। 23 नवम्बर को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी। इस दौरान विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया जाएगा। यात्रा के दौरान बालेन शाह भारतीय व्यापारियों और निवेशकों से संवाद करेंगे तथा उनसे नेपाल में निवेश करने का आग्रह करेंगे। इसी दिन दोनों देशों के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से जनकपुर-अयोध्या ट्रेन सेवा का उद्घाटन करेंगे।

संजना जाटव, दिव्या मदेरणा को राष्ट्रीय सचिव पद से हटाया

राजस्थान कांग्रेस के तीनों सह-प्रभारी हटाए, चार नए सह-प्रभारी सचिव लगाए

जयपुर (कासं)। राजस्थान कांग्रेस के तीनों सह-प्रभारी सचिवों को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह चार नेताओं को राजस्थान में सह-प्रभारी सचिव लगाया गया है। राजस्थान के 6 नेताओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया है, जबकि सांसद संजना जाटव, दिव्या मदेरणा सहित तीन नेताओं को पद से हटाया है। राजस्थान कांग्रेस के सह-प्रभारी सचिव चिरंजीव राव, ऋतिक मकवाना और पूनम पासवान को राष्ट्रीय सचिव व सह-प्रभारी पद से हटा दिया है। राजस्थान में चार राष्ट्रीय सचिवों को सह-प्रभारी लगाया है। कांग्रेस नेता विश्व विजय सिंह, पलक वर्मा, मनोज बागड़ी और पोरलक खारते को राजस्थान के सह-प्रभारी सचिव की जिम्मेदारी दी है। राजस्थान से 6 नेताओं को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। सेवा दल के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष हेम सिंह शेखावत, विधायक डूंगर राम गेदर, पूर्व विधायक धीरज गुर्जर, दानिश अबरार, जगदीश जांगिड़ और रेहाना रियाज को राष्ट्रीय सचिव बनाकर राज्यों में सह-प्रभारी बनाया है। हेम सिंह शेखावत और डूंगर राम गेदर को पहली बार जिम्मेदारी दी गई है। सांसद संजना जाटव, पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा और विजय जांगिड़ को राष्ट्रीय सचिव पद से हटा दिया है। दिव्या मदरेणा के पास जम्मू-कश्मीर के सह-प्रभारी सचिव की जिम्मेदार थी। इस बदलाव को लेकर सियासी हलकों में चर्चा हो रही है। राजस्थान से राष्ट्रीय सचिव बनाए गए 6 नेताओं को राज्यों में सह-प्रभारी बनाया गया है। हेम सिंह शेखावत को गुजरात, धीरज गुर्जर को जम्मू-कश्मीर, दानिश अबरार को दिल्ली, जगदीश जांगिड़ को उत्तर प्रदेश, डूंगर राम गेदर को मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम और रेहाना रियाज को महाराष्ट्र के सह-प्रभारी सचिव की जिम्मेदारी दी है।

तिरूपरनकुंद्रम पहाड़ी पर एक बार दीप जलाने की मिली अनुमति

नई दिल्ली (एजेंसी)। तमिलनाडु के मदुरै में तिरूपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की परंपरा को लेकर विवाद चल रहा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम व्यवस्था के तहत, 24 नवंबर 2026 को तमिलनाडु के मदुरै में तिरूपरनकुंद्रम पहाड़ी पर मौजूद पत्थर के खंभे, जिसे 'दीपाथून' कहा जाता है, वहां पारंपरिक 'कार्तिगई दीपम' जलाने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये अंतरिम अनुमति ऐसे समय में दी है जब पहाड़ी के मालिकाना हक और अनुष्ठान की जगह को लेकर हिंदू श्रद्धालुओं और हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह औलिया दरगाह के बीच विवाद चल रहा है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने दीप जलाने की अनुमति के साथ ही मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले के कुछ हिस्सों पर रोक लगा दी है, जिसमें 'दीपाथून' पर दीप जलाने की परंपरा को फिर से शुरू करने के निर्देश को सही ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गुरूवार को दरगाह की ओर से दी गई दलीलों के बाद सामने आया है। दरगाह ने पूरी पहाड़ी पर अपना मालिकाना हक जताया और पत्थर के खंभे पर दीप जलाने की मांग का विरोध किया। इस मामले पर गुरूवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी थी और कोर्ट ने शुक्रवार को आगे की कार्यवाही जारी रखने का फैसला किया।

पंचायतीराज चुनाव की मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न, जिला परिषद एवं पंचायत समितियों के परिणाम घोषित

जिला परिषद में कांग्रेस ने 41, भाजपा ने 12 एवं आरएलपी ने 2 वार्डों में दर्ज की जीत

22 पंचायत समितियों में कांग्रेस के 216, भाजपा के 87, आरएलपी के 60 एवं अन्य के 20 सदस्य निर्वाचित

ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण 5 मतदान केंद्रों पर 22 नवंबर को होगा पुनर्मतदान



जयपुर (कासं)। पंचायतीराज आम चुनाव-2026 के तहत जयपुर जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए शुक्रवार को सीकर रोड स्थित श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में मतगणना हुई। जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) संदेश नायक ने बताया कि जिला परिषद के कुल 57 वार्डों में से 55 वार्डों के परिणाम घोषित किए गए हैं। इनमें कांग्रेस ने 41, भारतीय जनता पार्टी ने 12 तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने 2 वार्डों में जीत दर्ज की है। इसी प्रकार जिले की 22 पंचायत समितियों के कुल 386 वार्डों में से 383 वार्डों के परिणाम घोषित हुए हैं। इनमें कांग्रेस के 216, भाजपा के 87, आरएलपी के 60 तथा अन्य के 20 सदस्य निर्वाचित हुए हैं। मतगणना के दौरान ईवीएम में तकनीकी खराबी के कारण जिला परिषद के दो एवं पंचायत समितियों के तीन वार्डों के परिणाम घोषित नहीं हो सके। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 13 के बूथ संख्या 60 एवं निर्वाचन क्षेत्र संख्या 52 के बूथ संख्या 81 तथा पंचायत समिति दूदू के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 06 के बूथ संख्या 62, शाहपुरा के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 06 के बूथ संख्या 34 एवं चौमूं के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 25 के बूथ संख्या 142 पर पुनर्मतदान के आदेश जारी किए हैं। आयोग के निर्देशानुसार इन पांचों मतदान केंद्रों पर 22 नवंबर 2026 को प्रात: 7 बजे से सायं 6 बजे तक पुनर्मतदान करवाया जाएगा। पुनर्मतदान के पश्चात उसी दिन रात्रि 9 बजे से मतगणना प्रारंभ होगी। जिला परिषद के संबंधित वार्डों की मतगणना जिला मुख्यालय पर तथा पंचायत समिति सदस्यों की मतगणना संबंधित पंचायत समिति मुख्यालयों पर करवाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने पंचायतीराज चुनावों को पूर्ण निष्पक्षता, शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न कराने पर निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी कार्मिकों, जनप्रतिनिधियों एवं आम मतदाता का आभार व्यक्त किया है।

राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर 20 नवंबर को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश की पंचायत समितियों के कुल 7,543 वार्डों में से 7,386 के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इनमें कांग्रेस ने 3,700 और भाजपा ने 2,177 सीटें जीती हैं। दोनों दलों के बीच 1,532 सीटों का अंतर है।

पंचायत समिति चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने 625 सीटें जीती हैं। आरएलपी को 496, भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) को 276 , बसपा को 60, माकपा को 50 और आम आदमी पार्टी को दो सीटें मिली हैं। इस तरह पंचायत समिति चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के अलावा क्षेत्रीय दलों तथा निर्दलीय उम्मीदवारों की भी उल्लेखनीय मौजूदगी रही है। कुल 7,543 वार्डों में से 157 के परिणाम अभी घोषित होना बाकी हैं। जिला परिषद सदस्य चुनाव में भी कांग्रेस ने भाजपा पर बढ़त बनाई है। कुल 1,275 सीटों में से अब तक 981 के परिणाम घोषित हुए हैं।

इनमें कांग्रेस ने 599 और भाजपा ने 301 सीटें जीती हैं। दोनों दलों के बीच 298 सीटों का अंतर है। जिला परिषद चुनाव में आरएलपी को 37 बीएपी 22 और निर्दलीय उम्मीदवारों को 10 सीटें मिली हैं। बसपा-माकपा ने 6-6 और बीएपी ने 22 सीट जीती है।

पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली प्रचण्ड जीत भाजपा का सूपड़ा साफ- डोटासरा



जयपुर (कासं)। राजस्थान में हुये पंचायत राज संस्थाओं के चुनावों की मतगणना के पश्चात् कांग्रेस पार्टी को मिली प्रचण्ड जीत की प्रदेशवासियों को बधाई देते हुये राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जीत प्रदेश की जनता की है और कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा की गई मेहनत का परिणाम है। प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय के चुनावों में अधिकांशत: जिस पार्टी की सत्ता होती है उसके पक्ष में जाते हैं, आज पंचायती राज संस्थाओं के जारी परिणामों में राजस्थान से भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया और प्रदेशवासियों ने भाजपा सरकार को पूरी तरह से नकार दिया है। प्रदेश की जनता ने आज यह बता दिया है कि विधानसभा चुनावों में भाजपा पर भरोसा कर गलती ही नहीं बल्कि महान् गलती की थी, जिसका ब्याज सहित आज भाजपा को हराकर चुका दिया है। नगर निकाय के चुनावों में बेईमानीपूर्वक परिसीमन करने के बावजूद कांग्रेस के बराबर मत प्रतिशत मिलने पर भी ज्यादा बोर्डों में भाजपा के चेयरमेन सत्ता का दुरूपयोग और पुलिस की सहायता से बना दिये थे, जिसका जवाब भाजपा को आज पंचायती राज चुनावों में मिला है। नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी के बराबर मत प्रतिशत मिलने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और भाजपा के केन्द्रीय नेताओं ने छद्म परसेपशन बढऩे के लिये प्रचण्ड जीत बताई थी, आज जनता ने देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के हाईकमान व प्रदेश के मुख्यमंत्री को प्रचण्ड हार देकर प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पर किये गये ट्विट का जवाब प्रदेशवासियों ने दिया है। पंचायती राज संस्थाओं में जो आज परिणाम जारी हुये हैं वह आज तक की इतिहास में नहीं आये, क्योंकि तीन साल से राजस्थान की जनता भाजपा का कुशासन झेल रही थी और भाजपा नेताओं का बोझ सहते हुये कराह रही थी। प्रदेश में मंहगाई बढ़ रही है, अस्पतालों में हमारी बहिन-बेटियां प्रसव के लिये गई उनकी मौत हो गई, जर्जर भवन गिरने से स्कूली बच्चों की मौत हो गई, किसान खाद् और बीज के लिये परेशान थे, लेकिन भाजपा सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं थी, ये सभी घोटालों को करने में लिप्त रहे, नौजवान नौकरी मांगने गया तो उसके बदले में लाठियां मिली, लेकिन घोषणायें और दावे बड़े-बड़े किये गये लेकिन धरातल पर जनता को कुछ नहीं मिला। मुख्यमंत्री तीन साल के शासन में केवल कांग्रेस को कोसने का काम करते रहे, मगरमच्छ और पेपर लीक का अलाप करते रहे, लेकिन एक दिन जनता की सुनने के लिये समय नहीं निकाला। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेन्स की बात करने वाले लोग मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठने वाले लोग मुख्यमंत्री की नाक के नीचे उनके हस्ताक्षर कराकर भ्रष्टाचार करते रहे, अधिकारियों के 64 विला हो गये, लाभ देने के लिये मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर हो गये।

पंचायत चुनाव परिणामों पर मंथन करेगी भाजपा: राठौड़



जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव परिणामों को जनादेश के रूप में स्वीकार करती है। भाजपा का स्पष्ट मानना है कि कांग्रेस ने ये चुनाव विशुद्ध रूप से झूठ और फेक नैरेटिव के आधार पर लड़ा, जबकि भाजपा ने सकारात्मक राजनीति करते हुए विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच अपनी बात रखी। चुनाव परिणामों पर पार्टी सकारात्मक भाव से मंथन करेगी और आगे की रणनीति तय करेगी। राठौड़ ने कहा कि चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और उनके राष्ट्रीय आदर्श एवं लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा राहुल गांधी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने जिस तरह वोट चोरी का माहौल बनाया और संवैधानिक संस्थाओं पर छींटाकशी करते हुए अराजकता का वातावरण तैयार किया, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस लगातार ईवीएम, प्रशासन, चुनाव आयोग और भाजपा पर निराधार आरोप लगाती रही तथा देश के युवाओं को बरगलाने का प्रयास किया। आज चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस नेताओं का जश्न मनाना उनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है।

उदयपुर में भाजपा, राजसमंद-चित्तौड़ में कांग्रेस को बहुमत

प्रतापगढ़-डूंगरपुर बांसवाड़ा व सलूम्बर में किसी को बहुमत नहीं

संभाग के 7 जिलों में पंचायतीराज चुनाव में कांग्रेस सबसे बडी पार्टी उभरकर सामने आई है वहीं दूसरी और केन्द्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के बाद भी पंचायतीराज चुनाव में ग्रामीणों ने भाजपा को नकार दिया हैं। उदयपुर जिला परिषद में भाजपा को बहुमत मिला हैं। वहीं चित्तौडगढ जिले में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला हैं। इसके अलावा अन्य सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी बढ़त लेती नजर आई। हांलाकि बांसवाडा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूम्बर में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला लेकिन चित्तौडगढ़ में कांग्रेस ने एकतरफा जीत दर्ज की साथ राजसंमद जिला परिषद में कांग्रेस का दबदबा रहा। यहां पर कांग्रेस का जिला प्रमुख बनता नजर आ रहा हैं। उदयपुर जिला परिषद की कुल 47 सीटों में से भाजपा ने 24, कांग्रेस ने 22 और एक सीट पर बाप पार्टी ने जीत दर्ज की। चित्तौडगढ़ जिला परिषद के 35 वार्डों में कांग्रेस ने 28 सीटों पर जीत दर्ज कर स्पष्ट बढ़त बना ली, जबकि भाजपा केवल 7 सीटों पर सिमट गई। राजसमंद जिला परिषद की कुल 29 सीटो में से 17 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की जबकि भाजपा को 12 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा। डूंगरपुर जिला परिषद में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नही मिल पाया। यहां पर 37 वार्ड वाली डूंगरपुर जिला परिषद में भाजपा और भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) ने बराबर 14-14 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखाई, जबकि कांग्रेस 9 सीटों पर सिमट गई। यहीं हाल बांसवाडा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर का रहा।

बांसवाड़ा में जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस बहुमत से 1 सीट दूर रह गई। यहां जिला परिषद सदस्य के 43 में से 21 वार्ड पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। जिला प्रमुख बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 22 का है। पंचायतीराज चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ रही भारत आदिवासी पार्टी (बाप) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 17 वार्ड में जीत हासिल की। वहीं भाजपा महज 5 वार्डों में सिमट गई। प्रतापगढ जिला परिषद में स्पष्ट बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिला हैं।

कांग्रेस 11, भाजपा 7 और बाप पार्टी को 7 सीटे मिली हैं। इधर सलूम्बर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई हैं। यहां पर सबसे बडी पार्टी के रूप में भाजपा उभरकर सामने आई लेकिन 21 सीटों वाली जिला परिषद में भाजपा को 9, कांग्रेस को 8 और बाप पार्टी को 4 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा हैं।

उदयपुर संभाग के सात जिलों की पंचायत समितियो में बाप पार्टी ने उम्मीदों से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया हैं। कई पंचायत समितियों में बाप पार्टी के सदस्यों को भले ही बहुमत नहीं मिला हो लेकिन संख्या बल अधिक होने से वे निर्णायक की भूमिका में आ गए हैं। इसका लाभ कांग्रेस को मिलता दिखाई दे रहा हैं।

आरसीए चुनाव पर 7 दिसंबर को होगा फैसला

हाईकोर्ट ने बीसीसीआई को जारी किया नोटिस

जयपुर (कासं)। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव परिणामों का इंतजार कर रहे खिलाड़ियों और संबंधित पक्षों को अभी और प्रतीक्षा करनी होगी। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने इस मामले में अंतिम सुनवाई के लिए 7 दिसंबर की तारीख तय की है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। एसोसिएशन के पदों के लिए 29 सितंबर को मतदान हुआ था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के कारण मतों की गिनती और चुनाव परिणामों की घोषणा फिलहाल स्थगित है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने मामले से जुड़े सभी संबंधित पक्षकारों को निर्देश दिया है कि यदि किसी पक्ष ने अब तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है तो वे शीघ्र ही इसे अदालत के समक्ष पेश कर दें। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने मेघा गौड़ की पक्षकार बनने की अर्जी स्वीकार कर ली। इससे पूर्व मेघा गौड़ ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष याचिका दायर करके राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की चुनाव प्रक्रिया में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने का गंभीर विषय उठाया था। उनका तर्क था कि एसोसिएशन की मतदाता सूची में किसी भी महिला मतदाता अथवा महिला उम्मीदवार को स्थान नहीं दिया गया है। इस महत्वपूर्ण विषय पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी और राजस्थान उच्च न्यायालय को प्रक्रिया से जुड़े सभी कानूनी तथा व्यावहारिक मुद्दों पर त्वरित सुनवाई करके अंतिम निर्णय पारित करने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने अब इस पूरे विवाद में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी औपचारिक नोटिस जारी करके अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।



पुराना किला में पहले एससीओ सभ्यता संवाद का उद्घाटन, 15 देशों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा

वैश्विक शांति की गारंटी है सांस्कृतिक जुड़ाव- मोदी

नई दिल्ली (एजेंसी) । राजधानी के ऐतिहासिक पुराना किला में पहले शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सभ्यता संवाद का भव्य आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और वहां लगाई गई विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने महाभारत काल से लेकर 1200 ईस्वी तक के (लगभग 2100 वर्ष पुराने) ऐतिहासिक, पुरातात्विक साक्ष्यों और भारतीय संस्कृति व विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों को देखा।

इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर 15 देशों की सभ्यताओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद यह पहला अवसर है, जब पाकिस्तान के मंत्री भी किसी एससीओ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए भारत पहुंचे हैं।

कार्यक्रम में शामिल विदेशी अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जब दुनिया भर में युद्ध और अशांति की चर्चा हो रही है, ऐसे समय में भारत में सभ्यताओं के बीच संवाद हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वैश्विक शांति की सबसे मजबूत गारंटी सभ्यताओं के बीच संवाद और सांस्कृतिक जुड़ाव ही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ महीने पहले ही एससीओ ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए हैं। बीते ढाई दशकों में इस संगठन ने सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आपसी सहयोग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।

उन्होंने विश्वास जताया कि अब सदस्य देशों के बीच सांस्कृतिक संवाद इन संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाएगा, जिससे नए विचार और अवसर पैदा होंगे तथा दुनिया को एकजुट करने में मदद मिलेगी। आयोजन स्थल की महत्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि पुराना किला भारत की अद्भुत सांस्कृतिक धरोहर है, जिसकी ऐतिहासिक गाथाएं हजारों वर्ष पूर्व महाभारत काल तक जाती हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि साम्राज्यों ने दुनिया के नक्शे जरूर बदले हैं, लेकिन सभ्यताओं के बीच संवाद ने दुनिया के विचारों को बदला और उन्हें समृद्ध किया है। इसलिए एससीओ सभ्यता संवाद केवल एक औपचारिक मंच नहीं है, बल्कि यह दुनिया को नई दिशा देने का माध्यम बन सकता है। आज दुनिया में अंतरराष्ट्रीय सहयोग और लोगों के बीच आपसी जुड़ाव की काफी चर्चा होती है, लेकिन यह ऐसी सोच है, जिसे हमारे पूर्वजों ने सदियों पहले ही समृद्ध किया था। प्र.म.



मोदी ने प्राचीन व्यापारिक संबंधों का उदाहरण देते हुए कहा कि करीब पांच हजार साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध थे। बाद में दूसरे व्यापार मार्गों ने इस संपर्क को और विस्तार दिया। भारत, चीन, मध्य एशिया और यूरेशिया के कई क्षेत्र इन प्राचीन व्यापारिक नेटवर्क से जुड़े थे। इन रास्तों से केवल व्यापारी ही नहीं, बल्कि विद्वान और बौद्ध भिक्षु भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। इन यात्राओं के माध्यम से विचारों, भाषाओं और परंपराओं का आदान-प्रदान हुआ।

प्र.म. मोदी ने कहा कि 21वीं सदी की तकनीक ने दुनिया में सांस्कृतिक जुड़ाव की नई संभावनाएं पैदा की हैं। जिन रास्तों पर कभी हमारे पूर्वजों को महीनों यात्रा करनी पड़ती थी, आज उन्हीं देशों के लोग कुछ ही सेकंड में एक-दूसरे से जुड़ सकते हैं।

डिजिटल प्लेटफॉर्म ने ज्ञान साझाकरण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को पहले से आसान बना दिया है। एससीओ के देशों को इन नई संभावनाओं का पूरा लाभ उठाना चाहिए।

प्र.म. मोदी ने कहा कि हमारे देशों के संग्रहालयों, पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में हज़ारों वर्षों की अमूल्य विरासत सुरक्षित है। प्राचीन पांडुलिपियां, दुर्लभ पुस्तकें, ऐतिहासिक दस्तावेज़ और कलाकृतियां हमारे आपसी संबंधों के कई पहलुओं को उजागर करती हैं।

प्र.म. मोदी ने आगे कहा कि आज, तकनीक का उपयोग करके इस विरासत को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने के बेहतरीन अवसर मौजूद हैं। हम प्राचीन ग्रंथों के डिजिटलीकरण और अनुवाद के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। संयुक्त शोध परियोजनाओं के ज़रिए, हम अपने साझा इतिहास के नए पहलुओं को सामने ला सकते हैं। इससे दुनिया के किसी भी कोने में बैठा युवा किसी दूसरे देश की सांस्कृतिक विरासत को बेहतर ढंग से समझ सकेगा।

दैनिक लोकजीवन
जयपुर एवं भीलवाड़ा से एक साथ प्रकाशित
संस्थापक - स्व. डॉ. शिवकुमार जी किरोरी

क्वाड की नई रणनीतिक उड़ान

भारत के लिए मनीला शिखर सम्मेलन जहां रणनीतिक आश्वासन प्रदान करता है, वहीं क्वाड के विकसित होते एजेंडे को आकार देने का अवसर भी देता है। एक ऐसे लचीले समूह के प्रति नई दिल्ली की प्राथमिकता शिखर सम्मेलन के परिणामों में व्यापक रूप से परिलक्षित भी होती है। पहले क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम की मेजबानी से भारत को विनिर्माण, महत्वपूर्ण खनिजों, प्रौद्योगिकी, आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण में व्यापक अवसर मिलेंगे। हिंद महासागर में भारत के हितों की दृष्टि से समुद्री निगरानी सहयोग और समुद्र के भीतर बिछी केबल कनेक्टिविटी भी अहम है, जो सामुद्रिक निगरानी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की मजबूती जैसे उन बिंदुओं पर सहमति बनी है, जिनकी असल परीक्षा उन्हें अमल में लाने की होगी, क्योंकि उन्हें ठोस परिणामों में बदलने के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धता, पर्याप्त संसाधन और सार्थक क्षेत्रीय भागीदारी अनिवार्य है।

समग्रता में देखें तो क्वाड न तो पीछे हट रहा है और न ही स्थिर बना हुआ है, बल्कि वह स्वयं को एक ऐसे बदलते परिवेश के अनुरूप ढाल रहा है, जहां आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी प्रतिस्पर्धा और सामुद्रिक स्थिरता जैसे पहलू तेजी से आपस में जुड़ते जा रहे हैं। भारत के लिए यह पड़ाव अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को कायम रखते हुए रणनीतिक साझेदारियों को गहरा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। अंततः इस समूह के भविष्य से जुड़ी प्रासंगिकता भू-राजनीतिक संकेतों से आगे बढ़कर एक अधिक सुरक्षित, लचीले और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र को आकार देने की इसकी क्षमता पर ही निर्भर करेगी। आसियानशिखर सम्मेलन से इतर मनीला में आयोजित सातवां क्वाड शीर्ष नेतृत्व शिखर सम्मेलन इस संगठन की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनकर उभरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, आस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची को एक मंच पर लाने वाली इस बहुप्रतीक्षित बैठक में सदस्य देशों के सभी शीर्ष नेता करीब दो वर्षों से अधिक समय के बाद मिले। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह उनकी पहली क्वाड बैठक रही। इससे पहले भारत में 2025 की प्रस्तावित बैठक रद हो गई थी। उसके बाद से कायम अनिश्चितताओं को दूर करते हुए इस बैठक ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र के चार प्रमुख लोकतंत्रों के बीच रणनीतिक समन्वय के एक मंच के रूप में क्वाड की निरंतर बढ़ने वाली महत्ता को ही नए सिरे से पुष्ट करने का काम किया। इस शिखर सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण परिणति उन घोषणाओं को अमल में लाने पर सहमति बनने की रही, जिससे सभी सदस्य देशों के बीच रणनीतिक एकीकरण को व्यावहारिक सहयोग में बदला जा सके।

मनीला शिखर सम्मेलन में कई पहल की गईं। ये पहल क्वाड के विस्तारित होते रणनीतिक और आर्थिक एजेंडे को दर्शाती हैं। इस सिलसिले में 2027 में भारत की मेजबानी में मुंबई में आयोजित होने वाले पहले 'क्वाड बिजनेस लीडर्स फोरम' का उद्देश्य वाणिज्यिक साझेदारी को प्रगाढ़ बनाना, निवेश आकर्षित करना और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाना होगा। यह मंच नई दिल्ली को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में स्थापित करने का अवसर भी प्रदान करता है। इसी क्रम में इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सर्विलांस कोलैबोरेशन यानी आइप्र.म.एसएसी जैसी पहल सूचनाओं के आदान प्रदान और समुद्री क्षेत्र की निगरानी के स्तर को बेहतर बनाएगा। इसमें मार्च 2027 से चारों देशों के पी-8 और पी-3 सी गश्ती विमानों का एक प्रस्तावित संयुक्त अभ्यास भी शामिल है। इसके अलावा, 8.5 करोड़ डालर से अधिक के सहयोग से प्रस्तावित सुपर इंटेलिजेंस एक्सीलेरेटर का लक्ष्य पूरे क्षेत्र में विश्वसनीय एआइ तकनीक और तकनीकी सहायता तक पहुंच का विस्तार करना है, जो तकनीकी सहयोग की बढ़ती महत्ता को रेखांकित करता है। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने के अलावा निरंतर बढ़ते डिजिटल खतरों से निपटने के लिए सुरक्षित साइबर स्पेस को बढ़ावा देने पर भी बात हुई है। वैसे तो क्वाड बैठक में चीन का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया था, लेकिन शिखर सम्मेलन का रणनीतिक संदर्भ बिल्कुल साफ था। नेताओं ने आर्थिक दबाव, मनमाने निर्यात प्रतिबंधों और यथास्थिति बदलने के एकतरफा प्रयासों पर चिंता व्यक्त की। साथ ही समुद्री सुरक्षा, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया। बीजिंग का प्रत्यक्ष उल्लेख न करने की यह सोची-समझी रणनीति यही दर्शाती है कि चारों देशों को चीन-विरोधी गठबंधन के रूप में चिह्नित किए बिना ही परस्पर समन्वय को प्रगाढ़ बनाने की गुंजाइश मिलती रहे। यह भारत के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो अपनी रणनीतिक स्वायत्तता कायम रखते हुए अपनी रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करना चाहता है। महत्वपूर्ण खनिजों और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती पर बढ़ता जोर इसे रेखांकित करता है कि आर्थिक सुरक्षा किस तरह पारंपरिक सुरक्षा चिंताओं से एकीकृत होती जा रही है। सीमा-पार आतंक सहित हर तरह के आतंकवाद की स्पष्ट निंदा नई दिल्ली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद खतरे की आशंकाओं, आर्थिक प्राथमिकताओं और चीन के प्रति दृष्टिकोण को लेकर अब भी कुछ मतभेद हैं, जिसकी झलक दक्षिण और पूर्वी चीन सागर पर अपनाई गई अपेक्षाकृत अस्पष्ट भाषा में दिखाई देती है। असल में इसकी स्थायी ताकत क्वाड के एक औपचारिक सैन्य गठबंधन के रूप में विकसित होने के आसार बहुत ही कम दिखते हैं। इसके लचीलेपन और रणनीतिक एकीकरण से जुड़े व्यापक ढांचे के भीतर विभिन्न राष्ट्रीय हितों को समायोजित करने की क्षमता में ही कहीं अधिक निहित है।

बहुमत के अहंकार में संवाद की अनदेखी, जवाबदेही से ही मजबूत होगा लोकतंत्र

सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि पीएम मोदी ने कभी भी विपक्ष के आरोपों का सीधा जवाब नहीं दिया। ऐसे मौकों पर पीएम मोदी के बजाय भाजपा के नेता और मंत्री ही सवालों के जवाब आरोपों के अंदाज में देते रहे हैं। पीएम मोदी मन की बात या दूसरे मुद्दों पर सोशल मीडिया का ही उपयोग करते रहें हैं। संसद और बाहर उठाए गए सवालों के जवाब में सत्तारूढ़ भाजपा ने उल्टे सवाल पूछ कर मुद्दों को गोलमोल करने का प्रयास किया है।

गौरतलब है कि 2024 चुनाव से पहले भी राहुल समेत विपक्ष ने पूर्व जजों (मदन लोकुर, एपी शाह) के जरिए पीएम को लेटर लिखकर नेशनल सिक्योरिटी, अडानी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर डिबेट को कहा था, जिस पर पीएमओ की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपने दस साल के कार्यकाल के दौरान संसद को 48 बार संबोधित किया था। तब गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी ने उन्हें 'मौन मोहन' कहा था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी संसद में अब तक 22 बार ही बोले हैं। एचडी देवगौड़ा जो सिर्फ करीब दो साल के लिए प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी संसद में मोदी से ज्यादा बार बोला था। बीजेपी के ही अटल बिहारी वाजपेयी ने भी छह सालों में 77 बार संसद को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे में प्रेस के सवाल न लेने के फैसले पर विवाद रहा है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनस गार स्टोरे के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान नॉर्वे की एक महिला पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी से मीडिया के सवालों का जवाब देने का आग्रह किया था। लेकिन पीएम मोदी ने कोई सवाल नहीं लिया था। नॉर्वे की महिला पत्रकार हेला लेंग ने विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में भी मानवाधिकारों को लेकर सवाल उठाए। इस पर विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत एक सिवलाइजेशनल नेशन है।

इससे पहले हेला लेंग ने ओस्लो के गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टोर की प्रेस ब्रीफिंग खत्म होने के बाद खड़े होकर सवाल पूछा था। हेला ने पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवाल क्यों नहीं लेते? क्या आप हमारी सरकार के विश्वास के योग्य हैं? पीएम मोदी ने इन सवालों का कोई जवाब नहीं दिया था। हेला के सवाल पर भारत में भी काफी बहस रही। तब भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को आड़े हाथों लिया और पूछा कि सवालों से घबरा क्यों रहे हैं? इन विवादों को सुलझाने के लिए विदेश मंत्रालय ने भारत के लोकतंत्र का बचाव किया।

पीएम मोदी के इस दौरे में दूसरी बार था, जब इन मुद्दों पर सरकार को सफाई देनी पड़ी। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी 2026 के वर्ल्ड विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 180 देशों में 157वां स्थान मिला है। इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि प्रभावित होती है। सत्ता में बहुमत के बूते विपक्ष और मीडिया की आवाज को अनसुना करना देश के लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। इससे कहीं न कहीं सरकारी तंत्र में तानाशाही पनपने की संभावना रहती है। यही कारण भी है कि देश में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, सरकारी तंत्र का गैरजिम्मेदारी वाला आचरण नजर आता है। लोकतंत्र के लिए बेहतर तो यही होगा कि मोदी विपक्ष के साथ-साथ मीडिया के सवालों का भी जवाब दें।

वास्तविक लोकतंत्र वहीं होता है, जहां सत्तापक्ष विपक्ष और पत्रकारों के सवालों के जवाब दे। देश में सत्तापक्ष का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, इसलिए सवालों का अंतिम पड़ाव भी प्रधानमंत्री होता है। इस दृष्टि से भारतीय लोकतंत्र का यह पक्ष कमजोर माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सत्ता में आने के बाद से लगातार विपक्ष और पत्रकारों के सवालों की उपेक्षा के आरोप लगते रहे हैं। यह आरोप सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लगे हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष की आवाज दबाने के आरोपों का सामना लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को करना पड़ा है।

सर्वाधिक आश्चर्य की बात यह है कि पीएम मोदी ने कभी भी विपक्ष के आरोपों का सीधा जवाब नहीं दिया। ऐसे मौकों पर पीएम मोदी के बजाय भाजपा के नेता और मंत्री ही सवालों के जवाब आरोपों के अंदाज में देते रहे हैं। पीएम मोदी मन की बात या दूसरे मुद्दों पर सोशल मीडिया का ही उपयोग करते रहें हैं। संसद और बाहर उठाए गए सवालों के जवाब में सत्तारूढ़ भाजपा ने उल्टे सवाल पूछ कर मुद्दों को गोलमोल करने का प्रयास किया है। विपक्ष यही आरोप संसद सत्र के दौरान लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति पर लगाता रहा है। राहुल गांधी ने 3 दिन में 4 बार पीएम को मुद्दों पर बहस करने की चुनौती दी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर विदेशी ताकतों के दबाव में काम करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि मोदी विपक्ष पर देश विरोधी होने और विदेशी ताकतों से संबंध रखने के आरोप लगाते हैं, इसलिए उन्हें इन मुद्दों पर खुली बहस करनी चाहिए। राहुल ने बहस के लिए भारत-अमेरिका ट्रेड डील, देश की आर्थिक व्यवस्था, उद्योगपति गौतम अडाणी और जेफ्री एपस्टीन से जुड़े मुद्दे उठाए।

उन्होंने कहा कि बहस में देश के युवा और मीडिया भी मौजूद रहें। प्रधानमंत्री अपनी पसंद की जगह और जज चुन सकते हैं। राहुल गांधी ने संसद की कार्यवाही को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि सरकार चर्चा की बात करती है, लेकिन विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका नहीं देती। उन्होंने कहा कि जब वे बोलने की कोशिश करते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। 2 नवंबर को राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी को खुली बहस की चुनौती दी। इसी तरह 3 नवंबर को राहुल ने वीडियो जारी कर कहा कि मोदी को बहस की चुनौती दिए 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से जवाब नहीं आया। पंजाब के संगरूर में 4 नवंबर को कांग्रेस की इंसाफ रैली में राहुल ने फिर मोदी को चुनौती दी। राहुल ने दावा किया कि पांच मिनट की बहस में वे साबित कर देंगे कि मोदी 'देशद्रोही' हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नियंत्रण में हैं। राहुल के सवालों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब देने के बजाय उल्टे सात सुझाव दिए।

उन्होंने कहा कि अगर राहुल इन बातों पर अमल करें तो कांग्रेस संसद में ज्यादा सीटें जीत सकती है। रिजिजू ने कहा- राहुल को भाजपा को दुश्मन नहीं, राजनीतिक विरोधी समझना चाहिए। उन्हें भाजपा, आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति नफरत छोडकर संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने संसद का एक पुराना वीडियो भी शेयर किया। इसमें वे भाषण दे रहे हैं और विपक्षी सांसद सदन से उठकर जाते दिख रहे हैं। राहुल पहले भी बहस की चुनौती दे चुके हैं। राहुल ने अगस्त 2018 में कर्नाटक के बेलगाम में जनध्वनि रैली में राफेल मुद्दे पर कहा था कि मोदी जी और मेरे बीच राफेल पर बहस करा दो, मैं घंटों बोलूंगा। जनवरी 2019 में राहुल गांधी ने कहा कि राफेल पर लोकसभा में मुझे पीएम के साथ 20 मिनट वन टू वन बहस करने दो, अमरीका के प्रेसिडेंशियल डिबेट की तरह। साथ ही कहा था कि पीएम में हिम्मत नहीं है। 7 अप्रैल 2019 को भ्रष्टाचार पर मेनिफेस्टो लॉन्च पर मोदी के एक इंटरव्यू के बाद राहुल ने ट्वीट किया था कि आप भाग सकते हैं, लेकिन छिप नहीं सकते, मैं आपको भ्रष्टाचार पर बहस की चुनौती देता हूं।

संविधान सर्वोपरि, अतिवाद के लिए कोई जगह नहीं

भारतीय समाज पारंपरिक रूप में कुछ सामंती स्वरूप का रहा, पर संविधान ने उसके आधुनिकीकरण की राह तैयार की। संविधान में उसके दायरे के भीतर या बाहर देश में बदलाव लाने के लिए हिंसा का सहारा लेने वाले किसी भी समूह के लिए कोई स्थान नहीं था। इसलिए, जिन भी तत्वों ने अति-वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए बंदूक उठाई, उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। उनका मुकाबला करना अनिवार्य था। यह संतोषजनक है कि मोदी सरकार में माओवादी हिंसा के विरूद्ध मुहिम को सफलता मिली। माओवादी हिंसा के उन्मूलन में सुरक्षा बलों के शौर्य और मोदी सरकार की दृढ़ता को स्वीकार कर उन्हें श्रेय दिया ही जाना चाहिए।

जिस तरह हिंसा का समर्थन करने वाले धुर वामपंथी संवैधानिक मूल्यों को दरकिनार करते हैं, ठीक उसी तरह समाज और राजनीति में अतिवादी विचार थोपने वाले धुर दक्षिणपंथी भी संविधान की भावना से विमुख होते हैं। हमारा संविधान एक भविष्योन्मुखी दस्तावेज है और यही सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी माध्यम है। संविधान ने इस पहलू को स्वीकार किया कि भारतीय समाज के कुछ वर्गों ने ऐतिहासिक भेदभाव का सामना किया है। इसीलिए उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए इसने अफर्मेटिव एक्शन यानी आरक्षण जैसी व्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया। ऐसे में जो धुर दक्षिणपंथी ऊंच-नीच पर आधारित पुराने समाज की ओर लौटने में यकीन रखते हैं, उनके लिए भी लोकतांत्रिक भारतीय गणराज्य में कोई स्थान नहीं। धुर वामपंथ और धुर दक्षिणपंथ दोनों के अतिवादी कृत्य संविधान के अनुरूप नहीं हैं। धुर वामपंथी जहां क्रांति लाने के लिए हिंसक बदलाव के पैरोकार हैं, वहीं धुर दक्षिणपंथी सामाजिक क्षेत्र सहित लगभग सभी क्षेत्रों में अतीत की ओर देखते हैं। हिंसा उन सभी आदर्शों के बिल्कुल विपरीत है, जिनका संविधान प्रतिनिधित्व करता है। आस्था, समुदाय और जाति के आधार पर भेदभाव करने वाले कृत्य भी सीधे तौर पर संविधान के विरूद्ध हैं। भारत के संवैधानिक मूल्य और व्यवस्थाएं इतनी व्यापक और गहरी हैं कि वे सभी शिकायतों और समस्याओं का विवेकपूर्ण समाधान कर सकती हैं। यह समाधान भले ही तात्कालिक न हो और इसमें आपसी तालमेल एवं परस्पर विनिमय की प्रक्रिया शामिल



हो, लेकिन इसी व्यवस्था में ही व्यापक सद्भावना के साथ उन मुद्दों के भी हल निकाले गए हैं, जो कभी अनसुलझे प्रतीत होते थे।

आज सार्वजनिक विमर्श में जिस प्रकार की तनातनी महसूस होती है, वह स्पष्ट रूप से राजनीतिक वर्ग के बीच सार्थक संवाद की महत्ता को नए सिरे से रेखांकित करती है। ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में राजनीतिक वर्ग के लोग आपस में पर्याप्त संवाद नहीं कर रहे हैं। इसकी झलक संसद और राज्य विधानमंडलों के भीतर और बाहर, दोनों जगह दिखाई दे रही है। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि टीवी पर होने वाली जिन तल्ख बहसों में हिस्सा लेते हैं, उसे संवाद की संज्ञा तो नहीं दी जा सकती। इसी तरह डिजिटल माध्यमों पर एक-दूसरे के खिलाफ की जाने वाली छींटाकशी या ट्रोलिंग को भी संवाद नहीं कहा जा सकता। संवाद के लिए एक-दूसरे के दृष्टिकोण को समझने के साथ-साथ राष्ट्र की प्रगति के उद्देश्य से की जाने वाली शांत एवं गंभीर बातचीत की आवश्यकता होती है। संवैधानिक शासन के लिए सार्थक संवाद विशेष रूप से ऐसे समय में अनिवार्य है, जब भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को आगे ले जाने वाले सिद्धांतों को लेकर गहरे वैचारिक मतभेद मौजूद हों। संविधान और उसके मूल्य इन वैचारिक विभाजनों के बीच सामंजस्य बिठाने का आधार प्रदान करते हैं। ऐसा सामंजस्य इसलिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया बेहद तेजी वाले तकनीकी बदलावों के दौर से गुजर रही है और भारत गंभीर रणनीतिक चुनौतियों से भी घिरा हुआ है। संविधान नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने संबंधी सरकार के निर्णयों पर उच्चतर न्यायालय ही अंतिम निर्णायक होते हैं। किसी भी नागरिक को इस उद्देश्य से अदालतों का दरवाजा खटखटाने का अधिकार है। एक सामान्य नियम के तौर पर अदालतों ने यह माना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हिंसा के आह्वान या फिर समाज में विभाजन बढ़ाने वाली बातों को शामिल नहीं किया जा सकता। असल में वही लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर तय लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघते, जो संवैधानिक मूल्यों में अटूट आस्था रखते हैं। मगर कट्टरपंथी इन कसौटियों को नहीं मानते, फिर चाहे वे वाम खेमे के हों या दक्षिण टोले के। ऐसे तत्वों का बहिष्कार ही किया जाना चाहिए। वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है कि राजनीतिक वर्ग 'दिमागी संविधानवादी' बने। जब राजनीतिक वर्ग संविधान को ही अपना एकमात्र मार्गदर्शक मानकर उसके प्रति प्रतिबद्ध रहेगा, तभी राष्ट्र स्थायी शांति और प्रगति हासिल कर पाएगा। समय माओवादियों से त्रस्त रहे बस्तर में अर्धसैनिक बलों के साथ दीवाली मनाते समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने माओवाद से मुक्ति दिलाने में सुरक्षा बलों की सराहना करते हुए आगाह भी किया कि यह खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं, क्योंकि दिमागी नक्सलियों ने अन्य अनेक क्षेत्रों में भी अपनी पैठ बनाई हुई है। उन्होंने कहा कि आज भी वे देश के संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं और हमें इनकी पहचान करनी होगी, इन्हें परास्त करना होगा और राष्ट्र को पूरी तरह सुरक्षित बनाना होगा। मोदी के इन शब्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। भारत का लोकतांत्रिक संविधान महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित देश की आकांक्षाओं का प्रतीक है और इन आकांक्षाओं में सर्वप्रमुख आकांक्षा यही थी कि सभी भारतीय विशेषकर गरीब, वंचित और हाशिए के लोग अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के साथ सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण जीवन जी सकें।

महिला उद्यमिता दिवस मनाया, एमएसएमई और अर्थव्यवस्था में उनके बढ़ते योगदान को सराहा

जयपुर। भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक एक्सिस बैंक ने महिला उद्यमिता दिवस के अवसर पर अपने प्रमुख एमएसएमई सहभागिता मंच 'इवॉल्व' का विशेष संस्करण आयोजित किया। इसमें दिल्ली-एनसीआर की 110 से अधिक महिला-नेतृत्व वाली कंपनियों ने हिस्सा लिया। चर्चा में महिला-नेतृत्व वाले कारोबारों की जरूरतों और उन्हें अधिक आत्मविश्वास के साथ विस्तार करने में पूंजी तक पहुंच तथा उपयुक्त बैंकिंग समाधानों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया।

एक्सिस बैंक के एसएमई ग्राहकों में लगभग 28 प्रतिशत के कम से कम एक प्रवर्तक महिला हैं। यह एसएमई क्षेत्र में महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी को दर्शाता है। वहीं, एसएमई ग्राहकों में करीब 15 प्रतिशत ऐसे कारोबार हैं, जिनका पूर्ण स्वामित्व महिलाओं के पास है। बैंक के कुल एसएमई प्रवर्तक आधार में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 22 प्रतिशत है, जो कारोबार के स्वामित्व और उद्यमिता में उनकी बढ़ती मौजूदगी को रेखांकित करती है।

भारत के एमएसएमई क्षेत्र की विकास यात्रा में महिला उद्यमी एक सशक्त भूमिका निभा रही हैं। वे नवाचार, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में योगदान दे रही हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार, एमएसएमई का देश की जीडीपी में योगदान अब 31.1 प्रतिशत है। यह अर्थव्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। महिला उद्यमी भी इस विकास की गति का हिस्सा बन रही हैं और अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए औपचारिक ऋण का अधिकाधिक सहारा ले रही हैं। नीति आयोग, ट्रांसयूनियन सिबिल और माइक्रोसेव कंसल्टिंग की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार, 2017 से 2025 के बीच कारोबार के लिए महिलाओं को दिए जाने वाले ऋण में 7.5 गुना वृद्धि हुई। यह महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के बढ़ते पैमाने और महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है।

कारोबार बढ़ने के साथ उनकी वित्तीय जरूरतें भी केवल ऋण तक पहुंच तक सीमित नहीं रहतीं। कार्यशील पूंजी, नकदी प्रवाह का प्रबंधन, लेनदेन बैंकिंग, आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ाव, डिजिटल बैंकिंग और विस्तार के लिए पूंजी की जरूरत बढ़ने लगती है। एक्सिस बैंक का एमएसएमई प्रस्ताव कारोबारी सफर के विभिन्न चरणों में इन जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक समाधान उपलब्ध कराता है। कई महिला उद्यमियों के लिए संस्थागत ऋण हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसकी वजह उनके पास सीमित संपार्श्विक (कोलैटरल) का स्वामित्व, कारोबार का अपेक्षाकृत कम अनुभव और औपचारिक वित्तीय रिकॉर्ड में कमी होना है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए एक्सिस बैंक सीजीटीएमएसई समर्थित बिना संपार्श्विक वाले वित्तपोषण, सरल दस्तावेजी प्रक्रिया और डिजिटल ऑनबोर्डिंग की सुविधा देता है। बैंक औपचारिक ऋण तक पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल अंडरराइटिंग, नकदी प्रवाह आधारित आकलन और जीएसटी आधारित ऋण कार्यक्रमों का भी इस्तेमाल करता है।

औपचारिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ने के बाद कारोबारों की जरूरतें रोजमर्रा के कामकाज के प्रबंधन और विस्तार के वित्तपोषण तक पहुंच जाती हैं। महिला उद्यमियों के लिए बैंक 35 से अधिक एमएसएमई उत्पाद उपलब्ध कराता है। इन्हें 15 से अधिक डिजिटल प्रक्रियाओं का समर्थन प्राप्त है। इनमें चालू खाते, कार्यशील पूंजी और मियादी ऋण, व्यापार वित्त, विदेशी मुद्रा तथा नकदी प्रबंधन से जुड़े समाधान शामिल हैं। डिजिटल ऋण सुविधाओं में 20 लाख रुपये तक का मर्चेंट कैश एडवांस और जीएसटी आधारित ओवरड्राफ्ट समाधान शामिल हैं। बैंक महिला उद्यमियों के लिए कारोबार संबंधी विशेष बैंकिंग लाभ भी देता है। इनमें पात्र सीजीटीएमएसई समर्थित ओवरड्राफ्ट और मियादी ऋण पर ब्याज दर में 1 प्रतिशत की छूट तथा सुरक्षित उत्पादों पर 0.5 प्रतिशत की छूट शामिल है। ये लाभ लागू शर्तों के अधीन हैं। इन सुविधाओं के साथ संबंध-आधारित परामर्श भी दिया जाता है, जिससे कारोबारों को विस्तार के दौरान अपनी बैंकिंग और वित्तपोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलती है। कारोबारी जरूरतों के साथ-साथ बैंक 'अराइज' के जरिये महिलाओं की व्यापक वित्तीय जरूरतों को भी पूरा करता है। यह महिलाओं के लिए विशेष रूप से तैयार बचत खाता है।

अराइज में बचत, निवेश और ऋण समाधान शामिल हैं। इसके साथ वीसीआईपी के जरिये डिजिटल ऑनबोर्डिंग और स्वास्थ्य सेवा, लॉकर, एक्सिस डीमैट, क्रेडिट कार्ड तथा गोल्ड लोन जैसी सुविधाओं में 38,000 रुपये तक के लाभ मिलते हैं।

मजबूत एमएसएमई नेटवर्क के जरिये कारोबारों की वृद्धि को बढ़ावा

महिला उद्यमियों पर यह ध्यान बैंक की व्यापक एमएसएमई रणनीति का हिस्सा है। पहली बार ऋण लेने वालों और उभरते उद्यमियों से लेकर विस्तार के लिए पूंजी तलाश रहे स्थापित कारोबारों तक, एक्सिस बैंक वित्तपोषण, लेनदेन बैंकिंग और डिजिटल समाधानों के जरिये कारोबारों को सहयोग देता है। अपने वितरण नेटवर्क और डिजिटल बुनियादी ढांचे के दम पर बैंक प्रमुख एमएसएमई बाजारों में अपनी मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। इसमें वे बाजार भी शामिल हैं, जहां औपचारिक वित्त तक पहुंच सीमित है। एक्सिस बैंक का एमएसएमई पोर्टफोलियो फिलहाल लगभग 3.3 लाख करोड़ रुपये का है और इसमें 24 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज की गई है। बैंक की कुल बाजार हिस्सेदारी 8 प्रतिशत से अधिक है, जबकि नई वृद्धि के आधार पर यह 9 प्रतिशत से अधिक है। स्मॉल बिजनेस बैंकिंग (एसबीबी) पोर्टफोलियो 21 प्रतिशत की सालाना वृद्धि के साथ 85,167 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं, मिड-कॉरपोरेट अग्रिम में 29 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पोर्टफोलियो के विस्तार के साथ उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया गया है। एसएमई ऋणों में लगभग 84 प्रतिशत प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के मानकों के अनुरूप हैं और एसएमई ऋण पोर्टफोलियो के 84 प्रतिशत को एसएमई3 या उससे बेहतर रेटिंग मिली हुई है। वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही (एच1एफवाई27) में एसएमई के तहत मंजूर किए गए नए ऋणों में से 87 प्रतिशत को एसएमई3 या उससे बेहतर रेटिंग मिली। यह अनुशासित वृद्धि और जोखिम प्रबंधन पर बैंक के ध्यान को दर्शाता है। बैंक विभिन्न बाजारों में कारोबारों को सेवाएं देने के लिए डिजिटल प्रक्रियाओं और संबंध-आधारित बैंकिंग को भी साथ लेकर चल रहा है। बिना गारंटी वाले एसबीबी कारोबारी ऋणों के वितरण में लगभग 78 प्रतिशत हिस्सेदारी पूरी तरह डिजिटल ऋण प्रक्रिया की रही। वहीं, वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (क्यू2एफवाई27) में एसबीबी कारोबार में शाखाओं का योगदान लगभग 79 प्रतिशत रहा।

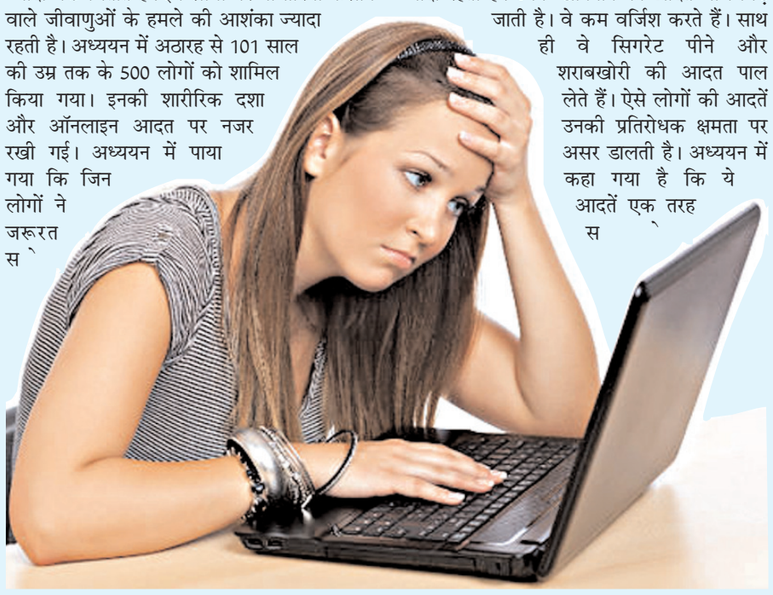
कुल मिलाकर, बैंक के नेटवर्क का व्यापक आकार, उसकी डिजिटल क्षमताएं और जमीनी स्तर पर मौजूदगी एक्सिस बैंक को विकास के विभिन्न चरणों में कारोबारों को सेवाएं देने और अधिक व्यापक बाजारों तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाती हैं। इस अवसर पर एक्सिस बैंक के ग्रुप हेड - मिड कॉरपोरेट एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ग्रुप, प्रशांत टी.एस. ने कहा, 'महिला उद्यमिता भारत के आर्थिक बदलाव की एक सशक्त ताकत के रूप में उभर रही है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) से मान्यता प्राप्त लगभग 47 प्रतिशत स्टार्टअप में कम से कम एक महिला निदेशक होना इस बात को दर्शाता है कि उद्यमों की स्थापना और नवाचार में महिलाएं किस तरह बढ़ती भूमिका निभा रही हैं। इस गति के साथ अब चर्चा को केवल वित्त तक पहुंच से आगे बढ़ाकर महिला-नेतृत्व वाले कारोबारों को विस्तार करने, प्रतिस्पर्धा करने और अपनी मजबूती विकसित करने में सक्षम बनाने पर केंद्रित करने की जरूरत है।

इसके लिए उन्हें औपचारिक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी, प्रौद्योगिकी अपनाने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद करनी होगी। एक्सिस बैंक में हमारा ध्यान वित्तीय समाधान, क्षेत्र-विशेष की विशेषज्ञता और उद्यमियों के साथ गहरे जुड़ाव के जरिये इस सफर में उनका समर्थन करने पर है।' एक्सिस बैंक के ग्रुप हेड - कमर्शियल बैंकिंग कवरेज ग्रुप, विजय शेट्टी ने कहा, 'आने वाले दशक में भारत की वृद्धि में देश के एमएसएमई क्षेत्र की मजबूती की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कारोबारों के विस्तार के साथ उनकी जरूरतें भी जटिल होती जाती हैं। इनमें

नेट की धुन में बड़े अवगुण

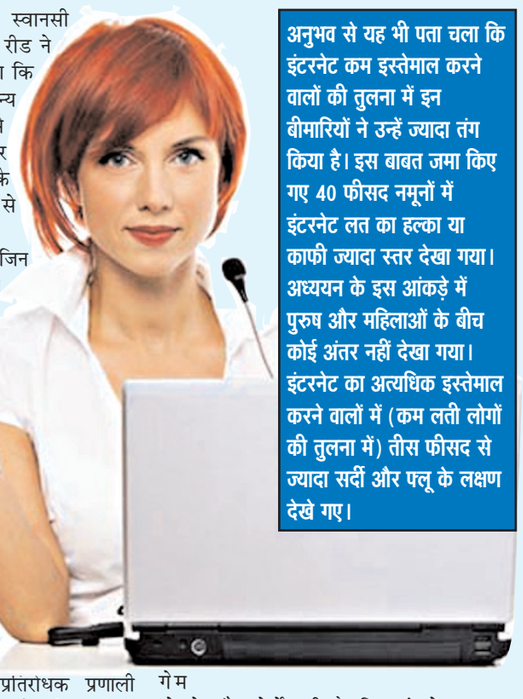
ऑन लाइन की लत आपकी सेहत चौपट कर सकती है। एक हालिया अध्ययन में दावा किया गया है कि जो लोग जरूरत से ज्यादा वक्त इंटरनेट पर बिताते हैं, उन्हें सर्दी, मौसमी बुखार की मार झेलनी पड़ सकती है। ऐसे लोगों की प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट के बेजा असर पर पहली बार कोई नतीजा सामने आया हो। कई देश युवाओं-बच्चों में इंटरनेट के प्रतिबढ़ती दीवानगी को लेकर पहले ही चिंता जता चुके हैं।

फिलहाल स्वानसी और मिलान विश्वविद्यालयों की ओर से कराए गए अध्ययन में पाया गया कि जो लोग इंटरनेट से थोड़ा परहेज रखते हैं, या कम वक्त गुजारते हैं, उन्हें फ्लू, सर्दी या मौसमी ज्वर का संक्रमण उन लोगों से कम होता है, जो इंटरनेट पर ज्यादा वक्त बिताते हैं। इन लोगों पर बीमारियां फैलाने वाले जीवाणुओं के हमले की आशंका ज्यादा रहती है। अध्ययन में अठारह से 101 साल की उम्र तक के 500 लोगों को शामिल किया गया। इनकी शारीरिक दशा और ऑनलाइन आदत पर नजर रखी गई। अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने जरूरत स



ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने की समस्या बताई, उन्होंने यह भी बताया कि इस लत के कारण उन्हें फ्लू और सर्दी जैसी समस्या ने घेर रखा है। उनके अनुभव से यह भी पता चला कि इंटरनेट कम इस्तेमाल करने वालों की तुलना में इन बीमारियों ने उन्हें ज्यादा तंग किया है। इस बाबत जमा किए गए 40 फीसद नमूनों में इंटरनेट लत का हल्का या काफी ज्यादा स्तर देखा गया। अध्ययन के इस आंकड़े में पुरुष और महिलाओं के बीच कोई अंतर नहीं देखा गया।

इंटरनेट का अत्यधिक इस्तेमाल करने वालों में (कम लती लोगों की तुलना में) तीस फीसद से ज्यादा सर्दी और फ्लू के लक्षण देखे गए। इससे पहले हुए शोध में जो लोग इंटरनेट से जरूरत से ज्यादा चिपके रहते हैं, उन्हें निद्रा में गड़बड़ी की शिकायत ज्यादा रहती है। उनके खानपान की आदत भी बिगड़ जाती है। वे कम वर्जिश करते हैं। साथ ही वे सिगरेट पीने और शराबखोरी की आदत पाल लेते हैं। ऐसे लोगों की आदतें उनकी प्रतिरोधक क्षमता पर असर डालती है। अध्ययन में कहा गया है कि ये आदतें एक तरह स



बीमारियों को बुलाती हैं। स्वानसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फिल रीड ने बताया कि अध्ययन से पता चला कि इंटरनेट का लोगों पर असर अन्य दूसरे मामलों से अलग थे, जैसे अवसाद, नींद में गड़बड़ी और एकाकीपन का नाता इंटरनेट के बेहद इस्तेमाल और खराब सेहत से जुड़ा देखा गया।

अध्ययन में बताया गया कि जिन लोगों को इंटरनेट की घोर आदत पड़ गई है, वे नेट से अलग होते ही काफी तनाव की जकड़ में आ जाते हैं और तनाव-राहत का यह चक्र कोर्टिसाल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ा देता है। इसका सीधा असर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। रीड का दावा है कि ऐसा भी हुआ है जिन्होंने इंटरनेट पर अकेले काफी वक्त बिताया, उनकी प्रांतरोधक प्रणाली कमजोर पड़ गई। लोगों से और उनके कीटाणुओं से ज्यादा संपर्क न होने के कारण ऐसा हुआ। अध्ययन में यह भी पाया गया कि जो लोग इंटरनेट का दिन में छह घंटे इस्तेमाल कर रहे थे, वे ज्यादातर सोशल साइटों पर रहे। नमूनों मे पाया गया कि काफी लोग ऐसे थे जिन्होंने दिन में दस घंटे तक इंटरनेट से साथ निभाया। अध्ययन के अनुसार, महिलाओं और पुरुषों में इंटरनेट इस्तेमाल करने के तरीके में भी फर्क देखा गया। मर्दों की तुलना में महिलाओं ने सोशल मीडिया और खरीदारी के लिए इंटरनेट का प्रयोग ज्यादा किया, या करती हैं। औरतों की तुलना में पुरुषों ने गेम खेलने और पोर्नोग्राफी के लिए इंटरनेट का लुत्फ उठाया। मिलान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रोबेर्टो ट्रूजोली ने कहा कि लैंगिक रूढ़िवादिता से अलग, इंटरनेट व्यवहार के नतीजे, प्रतिरोधक क्षमता पर इसके प्रभाव से जुड़े नही थे। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं पता लगता कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप इसका प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, तो आप बीमारियों के प्रति ज्यादा आशंकित हैं। हालांकि आप के बीमार होने के लिए कसूरवार कार्यप्रणाली अलग हो सकती है। यह निर्भर इस बात पर है कि आप नेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं।

अनुभव से यह भी पता चला कि इंटरनेट कम इस्तेमाल करने वालों की तुलना में इन बीमारियों ने उन्हें ज्यादा तंग किया है। इस बाबत जमा किए गए 40 फीसद नमूनों में इंटरनेट लत का हल्का या काफी ज्यादा स्तर देखा गया। अध्ययन के इस आंकड़े में पुरुष और महिलाओं के बीच कोई अंतर नहीं देखा गया। इंटरनेट का अत्यधिक इस्तेमाल करने वालों में (कम लती लोगों की तुलना में) तीस फीसद से ज्यादा सर्दी और फ्लू के लक्षण देखे गए।

स्किनी जींस पहनने के फायदे

बच सकते हैं कीमती सामान

बदलते दौर को देखकर अब पहले से ज्यादा यगंस्टर्स की फैशन में काफी बदलाव आता जा रहा है। समय में परिवर्तन के साथ अब महिला और पुरुष दोनों के फैशन में दिन व दिन बदलाव आ गया है। इन दिनों जहां पुरुष ढीले-ढाले कार्गो टाइप जींस पहनना अपनी अनोखी फैशन बना रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर महिलाएं नोर्मल जींस को छोड़ स्किनी जींस को अपना नया फैशन बनाने लगी हैं। लेकिन अब पुरुष और महिलाओं द्वारा भी स्किनी जींस पहनने की दूसरी वजह भी सामने आने लगी है। जी हां, और अगर आपने यह खबर पढ़ी तो आप भी कहीं न कहीं आप अपने आउटफिट्स में सबसे पहले स्किनी जींस को देंगे।



वजह है आपकी पॉकिट मनी और मोबाइल, पर्स आदि सुरक्षित रहना। अब आपके दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि आखिर एक स्किनी जींस किसी का मोबाइल, आईफोन या फिर पर्स कैसे सुरक्षित रख सकता है, तो हम आपको इसका कारण भी बताते हैं। दरअसल, हाल ही एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसमें एक जर्मन आर्किटेक की स्किनी जींस की वजह से आईफोन चोरी होने से बच जाता है। इसका खुलासा खुद उसी ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए इंटरव्यू में किया है। उसने कहा कि जिन दिन उसने स्किनी जींस पहन रखी थी, उस दिन उसकी पॉकिट में आईफोन6 था। उसकी कीमती आईफोन को देखकर तीन चोरों ने उसका पीछा तो किया लेकिन स्किनी जींस टाइट होने की वजह से उसका आईफोन नहीं चोरी कर पाए।

खुद के लिए सबसे माफी, सबको माफी



ध्यान रखें

- **क्षमा मांगने का अर्थ यह नहीं है कि आप गलत हैं और दूसरा सही। इसका अर्थ यह है कि आप अपने रिश्तों की कद्र करते हैं।**
- **किसी को माफ न करना, उस व्यक्ति के साथ न चाहकर भी अपने संबंध को बनाए रखना है। क्षमा से ही आप उस व्यक्ति से अपने बंधनों को हल्का करते हैं।**
- **माफी मांगते समय बहाने न बनाएं। ईमानदारी बरतें। विनम्र रहें।**
- **समय का ध्यान रखें। घाव भरने का समय दें और तब तक उस गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार रहें।**
- **माफी मांगते और माफ करते समय अहंकार भावना से दूर रहें।**



क्षमा को अहिंसा का अंग माना गया है। जैन दर्शन में इसे पर्व की तरह मनाया जाता है। यहां तक कि सभी धर्मों ने क्षमा को महान गुण माना है।

आधुनिक मोटिवेशनल गुरु भी हीलिंग प्रक्रिया में क्षमा को पहला कदम मानते हैं। वह कार्य, जो व्यक्ति को क्रोध और घृणा से मुक्त करके स्वस्थ जीवनशैली की ओर ले जाता है।

दिनभर में हम कई कार्य करते हैं। कुछ चेतना से तो कुछ अवचेतन मन से। और जब ध्यान कहीं और होता है तो गलतियां होती ही हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक और मानवीय है, उतना ही जितना गलतियों की माफी मांगना और दूसरों को माफ कर देना। द असेंशियल यू की संस्थापक केलसे फ्रीजेल के अनुसार, आज लोग अपनी भावनाओं को मन में दबाकर नहीं रखते। सहानुभूति और संवेदनशीलता जैसे गुणों की जरूरत फिर से महसूस की जाने लगी है। आत्मविकास की यात्रा में अपनी गलतियों की पहचान जरूरी होती है।

क्षमा की ताकत

महावीर कहते हैं, क्षमा मांगना और क्षमा करना आध्यात्मिक शुद्धि है। जिसे आपने दुख पहुंचाया है, वह कोई अन्य नहीं, स्वयं आप है। सब आत्माएं समान हैं। वैज्ञानिक और साइकोलॉजिकल पहलुओं पर भी क्षमा का असर देखने को मिलता है। कई रोगों से निजात मिलती है। मानसिक विकास होता है। गुस्सा, चिंता और घृणा के टॉक्सिन दूर होकर सुकून देते हैं। क्षमा के बिना प्यार संभव नहीं और प्यार के बिना क्षमा संभव नहीं। ईमानदारी से मांगी गयी माफी अच्छे संबंधों और सफलता की ओर ले जाती है।

क्षमा करना भी है जरूरी

विवेकानंद कहते हैं, जब तमाम गलतियों के बाद हम खुद को प्यार करना नहीं छोड़ते, तो दूसरों के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते। गुस्से और कड़वाहट को मन में बनाए रखना हाथ में पकड़े हुए उस गर्म कोयले के समान है, जो अपना ही हाथ जलता है।

मोटिवेशनल गुरु वेन डायर कहते हैं- माफ करके आगे बढ़ने का अर्थ यह नहीं कि आप दुख देने वाली घटना, व्यक्ति या सबक को भूल जाएं। याद रखें मगर विचार की तरह द्वेष या बदले की भावना हावी न रहे।

खुद से भी मांगें माफी

क्या कभी खुद से माफी मांगी है? क्षमा विषय पर आठ वर्षों तक शोध करने वाली आरुन लजारे कहती हैं- हमें दूसरों के प्रति अच्छा बनना सिखाया जाता है, पर हम खुद के प्रति कठोर बने रहते हैं। अपने प्रति कई गलतियां करते हैं, जैसे... अनावश्यक चिंताओं में घिरे रहना। अपने ज्ञान को बढ़ने से रोकना। हर समय खुद को हीन मानना।

खुद से प्यार न करना। स्वस्थ जीवनशैली नहीं अपनाना। वह कार्य न करना, जिनसे आप अपनी और दूसरों की मदद कर सकते हैं।

शादीशुदा लोग ज्यादा कर रहे हैं खुदकुशी

इसे भारतीय परिवारों में लगातार घटती व्यक्तिगत सहनशीलता की नजीर कह लीजिये या 'सात जन्मों के बंधन' में बढ़ते अवसाद का डरावना सबूत, देश में कुंवारों की तुलना में शादीशुदा लोगों में जिंदगी से हार मानकर खुदकुशी की प्रवृत्ति ज्यादा है। इसे भारतीय परिवारों में लगातार घटती व्यक्तिगत सहनशीलता की नजीर कह लीजिये या 'सात जन्मों के बंधन' में बढ़ते अवसाद का डरावना सबूत, देश में कुंवारों की तुलना में शादीशुदा लोगों में जिंदगी से हार मानकर खुदकुशी की प्रवृत्ति ज्यादा है।



राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2014 में अपने जीवन का खुद अंत करने वालों में 65.9 फीसद विवाहित थे, जबकि 21.1 प्रतिशत ऐसे थे जो शादी के बंधन में नहीं बंधे थे। खुदकुशी करने वालों में 1.4 प्रतिशत लोग या तो तलाकशुदा थे या किसी वजह से अपने जीवनसाथी से अलग रह रहे थे। मनोचिकित्सक और विवाह सलाहकार डॉ. अभय जैन ने आज पीटीआई-भाषा से कहा कि ये आंकड़े भारतीय परिवारों के ताने-बाने में गंभीर बदलावों की ओर इशारा करते हैं। उन्होंने कहा, ''देश में सामूहिक परिवार तेजी से एकल परिवारों में तब्दील हो रहे हैं। इससे परिवारों में टकराव बढ़ रहा है और व्यक्तिगत सहनशीलता लगातार कम होती जा रही है।''

जैन ने कहा, ''यह देखा जा रहा है कि एकल परिवारों में रहने वाले ज्यादातर पति-पत्नी अपनी पेशेवर और निजी समस्याएं एक-दूसरे से साझा नहीं करते और उनसे अकेले ही जूझते रहते हैं। इससे वे अवसाद का शिकार हो जाते हैं और आखिरकार आत्महत्या जैसा भयावह कदम भी उठा लेते हैं।'' उन्होंने कहा, ''शादियां तब ही लम्बे समय तक कामयाबी से चल सकती हैं, जब पति-पत्नी परिवार में एक-दूसरे के योगदान को बराबर महत्व दें और अपनी समस्याओं पर आपस में खुलकर बातचीत करें।''

बढ़ते तनाव का नतीजा हैं 'रोड रेज' की घटनाएँ



भारतीय सड़कों पर बढ़ रहे रोड़ रेज ने आम आदमी की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रोड़ रेज ने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया हैं। लेट लतीफी और अनुशासनहीनता इस समस्या की मूल जड़ है। वहीं काम का बोझ भी लोगों का तनाव बढ़ा रहा है। जिसका खामियाजा रोड़ पर चलता बेकसूर आदमी भुगतता है। बढ़ती आबादी और गाड़ियों की बढ़ी संख्या से सड़कें अब छोटी लगने लगी हैं। सड़क पर चलना ऐसा लगता हैं, मानों डब्बे में चल रहे हैं। सड़क पर चलते समय हम किसी भी तरह की रियायत बरतने को तैयार नहीं होते। सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव और आगे निकलने की होड़ चिड़चिड़ापन पैदा करती है। इसका गुस्सा सड़क पर ऐसे लोगों पर निकलता हैं, जिनसे छोटी गलती हो जाती है। नतीजा बहस से शुरू हुआ विवाद हाथापाई से होते हुए जानलेवा हमले तक पहुंच जाता है।

पिछले दिनों दिल्ली की सड़कों पर ऐसी ही एक घटना घटी। गाड़ी में जरा सी खरोंच लगने पर ही मासूम बच्ची के सामने ही उसके पिता की हत्या कर दी गई। आए दिन दिल्ली की सड़कों पर ऐसी वारदातें देखने को मिलती हैं। दिन-ब-दिन गाड़ियों की बढ़ती संख्या ट्रैफिक का दबाव बढ़ा रही है। भारतीय सड़कों पर ट्रैफिक जाम सामान्य बात हो गई है। भारत में लगभग 80 हजार लोग हर साल दुर्घटना में मारे जाते हैं। लोगों का काफी समय सड़कों पर ट्रैफिक जाम में निकल जाता है। ऐसे में हर किसी को घर-दफ्तर जल्दी जाने या अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी होती है। नतीजा पहले बहस होती है फिर हाथापाई।

पिछले दशक में 212 प्रतिशत गाड़ियां सड़कों पर बढ़ी हैं उसके मुकाबले सड़कें सिर्फ 17 फीसदी ही बढ़ी हैं। ऐसे में ट्रैफिक जाम होना स्वाभाविक है। बढ़ती संपन्नता ने लोगों को विलासिता की ओर धकेल दिया है। आज गाड़ी खरीदना और रखना संपन्नता का प्रतीक बन गया है। गाड़ी पर एक छोटा सा निशान लगना भी लोगों को बर्दाश्त नहीं। उन्हें लगता है उनके स्टेटस पर निशान लग गया। यही विवाद का कारण बनता है।

मनोचिकित्सक की मानें तो लोगों की मानसिकता में आया यह बदलाव आर्थिक संपन्नता का नतीजा है जिसने लोगों को भौतिकवादी बना दिया है। अच्छी सोसाइटी में घर। वहां के नए माहौल में रचने बसने के लिए और आरामदायक जीवन के लिए गाड़ियां जरूरी हो गई हैं। ऐसे में इन्हें अपनी इंसानियत से प्यार न होकर भौतिक वस्तुओं से ज्यादा प्यार होता है। दिल्ली की सड़कों पर तो गाड़ी चलाना खतरों से खेलने जैसा है। ट्रैफिक के नियम पालन करने की बात आती है तो हर लाल बत्ती पर इसका उल्लंघन साफ देखा जा सकता है। लोग ट्रैफिक लाइट को अनदेखा कर निकल जाते हैं। रात 11 बजे के बाद तो ट्रैफिक सिग्नल मजाक बन कर रह गए हैं। वहीं अनुशासनहीनता से भी समस्या विकराल रूप ले चुकी है। लगभग हर दिन दस लाख कारें, बस, ट्रक, स्कूटर और मोटरबाइक सड़कों पर उतरते हैं, नतीजा ट्रैफिक जाम। लोगों में आगे निकलने की होड़ उन्हें उग्र बना देती है। सड़क पर चलते समय धैर्य बरतने का समय होता है। गाड़ी चलाने वालों को अनुशासित और सभ्य बनना होगा। ट्रैफिक नियमों का पालन करना होगा। सड़क पर बुरी से बुरी स्थिति को भी शांत मन से संभालना चाहिए। रोड रेज की समस्या तभी कम होगी जब सड़क पर चलते समय या गाड़ी चलाते समय लोग धीरज रखें। साथ में ट्रैफिक नियमों का ईमानदारी से पालन करें। सबसे बड़ी बात यह है कि समय पर घर से निकलें ताकि दफ्तर, स्टेशन या अपनी मीटिंग में सही वक्त पर पहुंच सकें।

क्या वेतन के मामले में पुरुषों से पीछे ही रह जाएंगी महिलाएं



महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन हासिल करने में और 70 साल का समय लग सकता है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने रविवार को कहा कि इस समय पुरुषों की तुलना में महिलाओं को औसतन 77 प्रतिशत का वेतन मिलता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अंतरराष्ट्रीय श्रम आयोग (आइएलओ) ने कहा कि लिंग के आधार पर वेतन में असमानता बई हुई है, ऐसा बच्चे और बिना बच्चों वाली दोनों तरह की महिलाओं के साथ है।

आमतौर पर, पुरुष जितना कमाते हैं उसकी तुलना में महिलाएं औसतन 77 प्रतिशत कमाती है और उच्च आयवर्ग की महिलाओं में यह खाई अधिक चौड़ी है। आइएलओ के निदेशक गाय राइडर ने एक बयान में कहा, '20 साल पहले की तुलना में क्या आज कामकाजी महिलाओं की स्थिति बेहतर है? इसका जवाब हां होगा। यह प्रगति क्या हमारी उम्मीदों जैसी है? इसका जवाब होगा, नहीं। बदलाव की बहस में हमें प्रगतिशील होने और महिलाओं को काम के अधिकार सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।' संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजंसी ने कहा है कि बिना किसी लक्षित कार्रवाई के वर्तमान दर पर महिला और पुरुषों के बीच आय समानता 2086 से पहले या अब से कम से कम 71 साल पहले हासिल नहीं की जा सकती।

वैश्विक स्तर पर, पुरुष और महिलाओं के बीच श्रम बाजार भागीदारी दर में केवल 1995 के बाद से मामूली गिरावट दर्ज की गई है। इस समय 77 प्रतिशत पुरुषों की तुलना में कुल महिलाओं में से लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं कामकाजी हैं। 1995 में यह अनुपात क्रमशः 80 प्रतिशत और 52 प्रतिशत का था। एक अनुमान के मुताबिक, जी-20 देशों में 2025 तक दस करोड़ और महिलाओं के श्रम क्षेत्र में जुड़ जाने का अनुमान है जिसके कारण पुरुष और महिलाओं के बीच भागीदारी का अंतर 25 प्रतिशत तक कम हो सकता है। आज महिलाएं सभी व्यापार में से 30 प्रतिशत से अधिक अपना व्यापार करती हैं लेकिन यह छोटे उद्योग में केंद्रित हैं। एजंसी ने बताया कि और अधिक सूक्ष्म स्तर पर, वैश्विक स्तर पर 19 प्रतिशत महिलाएं बोर्ड स्तर पर काम कर रही हैं और विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में केवल पांच प्रतिशत महिलाएं ही सीईओ पद पर कार्यरत हैं।

इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि मातृत्व सुरक्षा में भी सुधार हुआ है और महिलाओं को 14 सप्ताह की छुट्टी या अधिक का मातृत्व अवकाश देने वाले देशों का प्रतिशत अब 38 प्रतिशत से बढ़ कर 51 प्रतिशत हो गया है। हालांकि, वैश्विक स्तर पर काम करने वाली 80 करोड़ से अधिक महिलाओं में से लगभग 41 प्रतिशत को अभी भी मातृत्व सुरक्षा पर्याप्त रूप से नहीं मिल रही है।

जरा सोच लें किस मौके पर ठीक रहेगा कौनसा फैशन



किशोरों से लेकर युवाओं में फैशन के प्रति जबरदस्त उत्साह देखा जा सकता है। मगर कई बार फैशन के प्रति ज्यादा दीवानगी उन्हें हंसी का पात्र बना देती है। फैशन के प्रति दीवानगी अपनी जगह ठीक है पर फैशन के सही चलन पर भी ध्यान दें। फैशनेबल दिखने के फेर में युवा अपने आराम पर ध्यान नहीं दे पाते। फैशन के दबाव में कुछ ऐसे कपड़े पहन लेते हैं, जो दिन भर उन्हें परेशान करते हैं। लिहाजा फैशन के मामले में किसी की देखा-देखी न करें। जरूरी नहीं जो दूसरों पर अच्छी लग रही है, वह आप पर भी लगे।

हमेशा सही नाप के कपड़े पहनें। कपड़े न ज्यादा ढीले हों न कसे हुए। अपने कपड़े और जूते के साइज का ध्यान भी रखें। ऐसे कपड़े पहनें जो आपको आरामदायक और सहज लगें। ज्यादा ढीले कपड़े या ज्यादा कसे कपड़ों में आप बेहतर महसूस नहीं करेंगे। कपड़ों की फिटिंग कंधों से बेहतर होनी चाहिए। कैजुअल लुक में अक्सर युवा ऐसे कपड़े पहनते हैं जो उनका पूरा व्यक्तित्व बिगाड़ देती हैं। लिहाजा आप थोड़ा प्रयोग कर सकते हैं। प्रिंटेड शर्ट और टीशर्ट को डेनिम जींस के साथ पहने सकते हैं। आजकल प्रिंट फिर से फैशन में है। भीड़ से अलग दिखने के लिए जरूरी नहीं कि आप कई सारे रंगों को घालमेल कर पहनें या फिर बहुत सारी एक्सेसरीज पहनें। भीड़ से अलग दिखाना चाहते हैं तो अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार करें। साधारण कपड़ों को भी अगर बेहतर तरीके से पहना जाएं तो व्यक्तित्व बेहतर लगता है। कई सारे रंगों को मेल आपको भीड़ में हंसी का पात्र बना सकता है। हमेशा ऐसी चीजों पर ध्यान दें, जो आपको औरों की नजरों में बेहतर दिखाएं। एक समय में बहुत कुछ पहनने कोशिश न करें। हमेशा थोड़े में ही बेहतरी पर ध्यान रखें। बहुत ज्यादा फंकी लुक वाले कपड़े या बहुत ज्यादा एक्सेसरीज आपके पर्सनेलिटी को बिगाड़ सकती हैं। ऐसे जूते खरीदें जो आपके लुक को निखारें। बहुत ज्यादा फंकी जूते अच्छे नहीं होते। कैजुअल और फार्मल जूते हमेशा रखें। आउटिंग वगैरह के लिए कैजुअल जूते जैसे-स्पोर्ट शूज और स्नीकर्स बेहतर होते हैं।

कई युवा हमेशा ब्रांड के चक्कर में पड़े रहते हैं। हमेशा इसके फेर में न पड़ें। हर ब्रांडेड चीज जरूरी नहीं कि अच्छी है। आप साधारण कपड़ों में ही कई प्रयोग कर सकते हैं। हर फैशन में खुद को ढालें यह जरूरी नहीं। आप उसी चलन के सथ चलें जो आपकी पर्सनेलिटी को निखारे। फैशनेबल दिखना और फैशन का हिस्सा बनना अच्छी बात है, पर यह ध्यान रखें कि फैशन के चक्कर में कहीं आप जोकर न बन जाएं।

राजस्थान को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने पर जोर, परियोजनाओं की समीक्षा

पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान दें अधिकारीः दिया कुमारी

जयपुर (कासं)। उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन, कला-संस्कृति तथा पुरातत्व मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को पर्यटन भवन में राजस्थान की पर्यटन एवं सांस्कृतिक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यटन, कला एवं संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी और पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियाड़ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने पिछली बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की तथा आगामी बजट के लिए प्रस्तावित नई योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए सभी परियोजनाओं का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधाओं और बेहतर व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए।



दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान आने वाले प्रत्येक पर्यटक को सुरक्षित, सुविधाजनक और यादगार अनुभव मिलना चाहिए। इसके लिए पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा करने के साथ ही प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन संभावनाओं का प्रभावी प्रचार-प्रसार किया जाए। बैठक में आगामी प्रमुख आयोजनों की तैयारियों पर चर्चा की गई। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 3 से 6 दिसंबर तक आयोजित होने वाले लोक मंथन-2026 के लिए 20 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई है। पर्यटन विभाग को इसका नोडल विभाग बनाया गया है। वहीं, 8 दिसंबर को झुंझुनूं के खेतड़ी स्थित होटल अभयगढ़ में शेखावाटी हेरिटेज मीट आयोजित होगी। इसमें मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आयोजन में शेखावाटी की ऐतिहासिक हवेलियों के संरक्षण और नई योजनाओं की शुरुआत पर चर्चा प्रस्तावित है। 10 दिसंबर को आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस में 'राजस्थान-2047 : विरासत, नवाचार और वैश्विक अवसर' विषय पर पर्यटन सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग और लग्जरी पर्यटन की संभावनाओं पर चर्चा होगी। इसके अलावा जोधपुर और कोटा में संभाग स्तरीय लोक नृत्य उत्सव आयोजित किए जा चुके हैं। शेष संभागों में भी सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ऐसे आयोजन किए जाएंगे। वर्ष 2027 में जयपुर स्थापना के 300 वर्ष पूरे होने पर 'गोविंद देव जी कला महोत्सव' आयोजित करने की कार्ययोजना भी तैयार की जा रही है।

बैठक में राजस्थान ग्रामीण होमस्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) सब्सिडी योजना-2026, शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना-2026 और एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी की प्रगति की समीक्षा की गई। ग्रामीण होमस्टे योजना का संशोधित प्रारूप वित्त विभाग को भेजा गया है। इसमें पूंजीगत सब्सिडी के स्थान पर ब्याज सब्सिडी, सात वर्षों तक 75 प्रतिशत एसजीएसटी प्रतिपूर्ति तथा घरेलू दरों पर बिजली-पानी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव शामिल है। शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना का प्रारूप भी वित्तीय स्वीकृति के लिए भेजा गया है। एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी के लिए हितधारकों के साथ प्रारंभिक बैठक हो चुकी है तथा वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। वहीं, फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन योजना-2025 के तहत अब तक चार फिल्मों को सब्सिडी जारी की जा चुकी है।

67 बजट घोषणाओं में से 10 पूरी, 33 पर काम जारी

पर्यटन विकास से जुड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा में बताया गया कि कुल 67 बजट घोषणाओं में से 10 पूरी हो चुकी हैं, 33 पर कार्य प्रगतिरत है, आठ की स्वीकृति जारी हो चुकी है तथा 15 के प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जयपुर के आमेर-नाहरगढ़ क्षेत्र में एसएएससीआई परियोजनाओं के तहत 87 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। कुल 10 में से पांच कार्य पूरे किए जा चुके हैं। आमेर में साउंड एंड लाइट शो के लिए 13 नवंबर को अनुबंध हस्ताक्षरित किया गया है। वहीं, गैटोर की छतरियों का 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

युवाओं को शिक्षित बनाना और समाज को नशामुक्त करना राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी आवश्यकता - राज्यपाल

सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर 116 नवदंपतियों को दिया सुखी वैवाहिक जीवन का मंत्र

जयपुर/भरतपुर (कासं)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शुक्रवार को भरतपुर जिले के रूपवास क्षेत्र में बॉकाली मोड़ स्थित मां केला देवी स्टोन क्रेशर परिसर में आयोजित 116 बेटियों के सामूहिक विवाह समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने बगलामुखी राष्ट्र रक्षा महायज्ञ की पूर्णाहुति कार्यक्रम में भी भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल बागडे ने कहा कि 116 बेटियों का सामूहिक विवाह उत्सव सामाजिक समरसता, सहयोग और सेवा भावना का प्रेरणादायी उदाहरण है।

उन्होंने इस आयोजन को युवा महोत्सव की संज्ञा देते हुए आयोजकों की सराहना की। उन्होंने विशेष रूप से मुस्कान के पिता एवं अन्य आयोजकों के उस निर्णय की प्रशंसा की, जिसके तहत अपनी बेटी का विवाह भव्य सामूहिक आयोजन में कर गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग का अनुकरणीय संदेश दिया गया।



राज्यपाल ने शिक्षा को व्यक्ति, परिवार और राष्ट्र की प्रगति का आधार बताते हुए कहा कि विवाह समारोहों में होने वाली अनावश्यक फिजूलखर्ची पर रोक लगाकर उस धनराशि को बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए। बेटे-बेटियों को अच्छी शिक्षा और संस्कार देकर इस योग्य बनाएं कि वे भविष्य में रोजगार, उद्योग एवं अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़कर आत्मनिर्भर बन सकें तथा देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षित और संस्कारवान युवा ही सशक्त समाज एवं विकसित राष्ट्र की मजबूत नींव हैं।

राज्यपाल ने भारतीय संस्कृति में विवाह को महत्वपूर्ण संस्कार बताते हुए कहा कि भारतीय परंपरा में विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का भी मिलन है। उन्होंने शादियों में दिखावे और अनावश्यक खर्च से बचने तथा सादगीपूर्ण आयोजनों को प्रोत्साहित करने की अपील की। नवदंपतियों को सुखी वैवाहिक जीवन का मंत्र देते हुए राज्यपाल ने कहा कि दांपत्य जीवन में आपसी समझ, प्रेम, विश्वास और धैर्य का विशेष महत्व है।

यदि पति-पत्नी में से किसी एक को क्रोध आए तो दूसरे को शांत रहकर परिस्थिति को संभालना चाहिए। इससे परिवार में प्रेम और सौहार्द बना रहता है। उन्होंने सभी 116 नवदंपतियों के सुखी, स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की।

वैश्विक सुशासन में एशिया की बढ़ती भूमिका का प्रतीक सियोल सम्मेलन- मुख्य सचिव

सियोल/जयपुर (कासं)। राजस्थान के मुख्य सचिव एवं अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान (आईआईएएस) के अध्यक्ष वी. श्रीनिवास ने आईआईएएस सियोल सम्मेलन-2026 को वैश्विक सुशासन में एशिया की बढ़ती भूमिका का प्रतीक बताया। कोरिया गणराज्य के सियोल में सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल मंचों और बड़े आंकड़ों के प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ। श्रीनिवास ने सम्मेलन में पांच अनुच्छेदों वाली सियोल घोषणा को अंगीकार किए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह घोषणा सामाजिक मूल्य को विकास के केंद्र में रखती है तथा सरकारों, व्यावसायिक जगत, नागरिक समाज, शिक्षाजगत और स्थानीय समुदायों के सहयोग से सामाजिक समस्याओं के समाधान एवं संस्थागत बदलाव को आगे बढ़ाने पर बल देती है। उन्होंने विभिन्न देशों में शासन की गुणवत्ता का आकलन करने वाले आईआईएएस सुशासन सूचकांक को संस्थान की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इसके लिए उन्होंने संस्थान के वैज्ञानिक निदेशक प्रो. मार्को डे ला क्रूज के योगदान की सराहना की। मेक्सिको सिटी में वर्ष 2027 में होने वाले आईआईएएस सम्मेलन का उल्लेख करते हुए श्रीनिवास ने सदस्य देशों एवं संस्थाओं के साथ निरंतर संवाद और शासन को सरल बनाने में सहायक शोध आधारित पद्धतियों के विकास पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षाविदों और प्रशासकों के बीच वैश्विक सेतु के रूप में आईआईएएस की भूमिका को भी रेखांकित किया।



श्रीनिवास ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करने के लिए कोरिया गणराज्य की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष, आंतरिक एवं सुरक्षा मंत्री, अर्थशास्त्र, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संबंधी राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष तथा एसके समूह के अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया। उन्होंने सम्मेलन के सभी सत्र अध्यक्षों और शोधपत्र प्रस्तुत करने वाले 373 प्रतिनिधियों को भी धन्यवाद दिया। इस अवसर पर उन्होंने सत्र अध्यक्षों को सम्मेलन प्रमाणपत्र एवं स्मृति चिह्न प्रदान किए।

शहर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए फील्ड में उतरे जोन उपायुक्त

एक ही दिन में 575 ओपन कचरा डिपो किए साफ

जयपुर (कासं)। शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और खुले में कचरा डालने की प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नगर निगम जयपुर की टीम शुक्रवार को फील्ड में रही। आयुक्त ओम कसेरा के निर्देश पर सभी जोन उपायुक्त एवं सफाई से जुड़ी टीमें सुबह से ही अलर्ट मोड पर रहीं। सभी जोन उपायुक्त सुबह 7 बजे से ही फील्ड में उतर गए और विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं उपस्थित रहकर सफाई कार्यों की मॉनिटरिंग की। अधिकारियों ने मौके पर खड़े रहकर सफाई कार्य करवाया तथा कचरे के ढेर हटवाकर शहर को स्वच्छ बनाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की। शुक्रवार को नगर निगम की टीमों ने शहरभर में एक ही दिन में 575 ओपन कचरा डिपो की सफाई करवाकर लगभग 400 टन कचरे का निस्तारण किया।

विभिन्न क्षेत्रों में विशेष सफाई संसाधन एवं कार्मिक लगाकर खुले में पड़े कचरे को हटाया गया। निगम की इस त्वरित कार्रवाई से अनेक स्थानों पर सफाई व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला। आयुक्त ओम कसेरा ने सभी जोन उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे नियमित रूप से फील्ड में रहकर सफाई व्यवस्था की निगरानी करें तथा ओपन कचरा डिपो पर विशेष ध्यान देते हुए समयबद्ध तरीके से सफाई सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर अधिकारी निरंतर सक्रिय रहें और सफाई कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाए। नगर निगम जयपुर ने शहरवासियों से अपील की है कि वे खुले में, सड़क किनारे अथवा सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फेंकें।

पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए दिसंबर के प्रथम सप्ताह से ऑनलाइन प्रोग्राम

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधिमंडल के साथ की अहम बैठक

जयपुर (कासं)। राजस्थान पुलिसकर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए दिसंबर के प्रथम सप्ताह से मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी (यूके) के सहयोग से ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके तहत यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ पुलिसकर्मियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य संबंधी ऑनलाइन कक्षाएं लेंगे। इसके बाद प्राप्त परिणामों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जाएगा। इससे पुलिसकर्मियों की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को समझने और उनकी कार्यक्षमता में सुधार के लिए प्रभावी कदम उठाने में मदद मिलेगी। इस संबंध में शुक्रवार को पुलिस मुख्यालय सभागार में महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के प्रतिनिधिमंडल के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ग्लोबल मेंटल हेल्थ रिसर्च के प्रोफेसर विमल कुमार शर्मा ने किया। बैठक में 28 जुलाई, 2026 को राजस्थान पुलिस अकादमी और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के बीच हुए एमओयू के क्रियान्वयन तथा



आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। डीजीपी शर्मा ने कहा कि प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के साथ यह साझेदारी राजस्थान पुलिस के लिए महत्वपूर्ण पहल है। राजस्थान पुलिस के व्यापक अनुभव एवं उपलब्ध डेटा तथा विश्वविद्यालय की शोध विशेषज्ञता के समन्वय से पुलिसिंग, पुलिस कल्याण, मानसिक स्वास्थ्य और प्रशिक्षण के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। इससे पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञता और वैज्ञानिक शोध का लाभ मिलेगा। इस सहयोग के तहत पुलिसकर्मियों के लिए डिस्टेंस लर्निंग, सर्टिफिकेट कोर्स, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाओं और विशेषज्ञ व्याख्यानों के अवसर भी विकसित किए जाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य, तनाव प्रबंधन, सामाजिक देखभाल एवं स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में संयुक्त शोध से पुलिस कल्याण की भावी योजनाओं को भी नई दिशा मिलेगी। बैठक में मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से प्रो. कीथ ब्रेनन, प्रो. कैथरीन ए. रॉबिन्सन, प्रो. लूसी बर्न-डेविस, डॉ. इंगो शिसल, हेलेन हॉथॉर्न एवं डॉ. महेश एम. ओडियूर शामिल हुए। राजस्थान पुलिस की ओर से अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध शाखा) बिपिन कुमार पाण्डेय, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आलोक कुमार वशिष्ठ तथा उप महानिरीक्षक पुलिस (प्रशिक्षण) शरद चौधरी उपस्थित रहे।

राज्य स्तरीय कमांडेंट कॉन्फ्रेंस में स्वयंसेवकों के नियोजन को बढ़ाने पर जोर

जयपुर (कासं)। गृह रक्षा विभाग, राजस्थान की राज्य स्तरीय कमांडेंट कॉन्फ्रेंस गुरुवार 19 नवंबर को केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान (सीटीआई), फतेहपुरा बेगस, जयपुर में आयोजित हुई। महानिदेशक एवं महासमादेष्टा गृह रक्षा अनिल पालीवाल (आईपीएस) की अध्यक्षता में आयोजित इस कॉन्फ्रेंस में विभाग के प्रशासनिक, वित्तीय एवं कार्यप्रणाली से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा की गई। बैठक में स्वयंसेवकों के नियोजन में वृद्धि, पारदर्शी ड्यूटी रोटेशन और जिला इकाइयों में अनुशासन सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया।

कॉन्फ्रेंस के दौरान महानिदेशक एवं महासमादेष्टा पालीवाल ने प्रदेश के विभिन्न जिला प्रशिक्षण केन्द्रों से आए समादेष्टाओं के साथ व्यक्तिगत संवाद किया। उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर कार्य संचालन में आ रही समस्याओं और चुनौतियों के बारे में जानकारी ली तथा समादेष्टाओं से सुझाव प्राप्त किए। साथ ही



समस्याओं के त्वरित एवं व्यावहारिक समाधान के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और दिशा-निर्देश दिए।

बैठक में सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू), निजी कंपनियों एवं प्रतिष्ठानों में गृह रक्षा स्वयंसेवकों के नियोजन के अवसर बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके लिए ऑनलाइन नियोजन सॉफ्टवेयर एचडीएमएस का प्रभावी उपयोग करने तथा ड्यूटी रोटेशन प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने

न्यूज इनबॉक्स

देवनानी से केरलम विधान सभा की युवा एवं युवा कल्याण समिति के सदस्यों ने की शिष्टाचार भेंट

जयपुर (कासं)। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से शुक्रवार को विधान सभा में केरलम विधानसभा की युवा एवं युवा कल्याण समिति के सदस्यों ने विधानसभा में शिष्टाचार भेंट की। देवनानी ने समिति के सदस्यों का अभिनन्दन कर विधान सभा का लोगो भेंट किया। केरलम विधानसभा की युवा एवं युवा कल्याण समिति के सभापति सनीश कुमार जोसफ ने स्पीकर देवनानी को केरलम विधान सभा की नियमावली भेंट की। देवनानी ने भी जोसफ को राजस्थान विधान सभा का साहित्य भेंट किया। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने संसदीय परंपराओं, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा विधायी संस्थाओं की भूमिका से जुड़े विभिन्न विषयों पर केरलम विधान सभा के सदस्यों से विचार-विमर्श किया। केरलम विधानसभा की युवा एवं युवा कल्याण समिति ने राजस्थान विधानसभा के सदन, भवन एवं संग्रहालय का अवलोकन किया। समिति के सदस्यों ने विधानसभा की कार्यप्रणाली, सदन की गरिमा, स्थापत्य कला एवं संसदीय परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। सदस्यों ने राजस्थान के राजनीतिक इतिहास, लोकतांत्रिक विकास, ऐतिहासिक घटनाओं तथा प्रदेश की संसदीय यात्रा से संबंधित प्रदर्शित सामग्री का अवलोकन किया और संग्रहालय की सराहना की। इस अवसर पर समिति के सदस्यों ने राजस्थान विधानसभा की समृद्ध संसदीय परंपराओं एवं ऐतिहासिक धरोहर को सराहनीय बताया।

लक्ष्मीनारायण सैनी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

जयपुर (कासं)। झुंझुनूं जिले की खेतड़ी थाना पुलिस ने चुनाव मतदान के दौरान पूर्व सरपंच लक्ष्मीनारायण सैनी की हत्या के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सुरेन्द्र सिंह और जयपाल सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी खेतड़ी थाने में मारपीट के दो-दो प्रकरण दर्ज हैं। मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका को लेकर अनुसंधान जारी है। एसपी कावेंद्र सिंह सागर ने बताया कि 17 नवंबर को परिवादी राजेश कुमार सैनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 16 नवंबर को चुनाव मतदान के दौरान उनके पिता लक्ष्मीनारायण सैनी पोलिंग बूथ के बाहर बैठे हुए थे। इसी दौरान सुरेन्द्र सिंह, जयपाल सिंह, दौलत सिंह, रणवीर सिंह और अन्य 5-7 व्यक्तियों ने एकराय होकर उन पर जान से मारने की नीयत से कुर्सियों से हमला कर दिया। हमले में लक्ष्मीनारायण सैनी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए पहले बबाई अस्पताल और बाद में नीमकाथाना अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक सागर के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय देवेन्द्र सिंह राजावत के मार्गदर्शन तथा खेतड़ी वृत्ताधिकारी राजेन्द्र कुमार बुरडक के सुपरविजन में थानाधिकारी बुद्धिप्रसाद के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने कार्रवाई करते हुए हत्या के मुख्य आरोपी जयपाल सिंह पुत्र पूर्ण सिंह (41) निवासी ढाणी आशाकाला और सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय श्योबक्स सिंह (50) निवासी ढाणी मीनावाली तन विजयनगर थाना खेतड़ी, जिला झुंझुनूं को गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण में आगे का अनुसंधान जारी है।

एसीएस माइंस ने खान विभाग के अधिकारियों को दिए सक्रियता बढ़ाने के निर्देश

जयपुर (कासं)। अतिरिक्त मुख्य सचिव खान एवं पेट्रोलियम श्रीमती अपर्णा अरोरा ने खान विभाग के फील्ड अधिकारियों को लक्ष्यानुसार शत-प्रतिशत राजस्व संग्रहित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रहण के सभी संभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर वसूली के कारगर प्रयास किये जाने हैं। खान विभाग का फोकस राजस्व लक्ष्यों को अर्जित करना है और इसके लिए विभागीय अधिकारियों को फील्ड में अधिक सक्रिय होने के साथ ही लीकेज के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जानी है। एसीएस खान श्रीमती अपर्णा अरोरा शुक्रवार को खनिज भवन में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की समीक्षा बैठक ले रही थी। विभाग द्वारा गत वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में अक्टूबर तक 12.98 प्रतिशत विकास दर के साथ करीब 809 करोड़ रूपये का अधिक राजस्व संग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य बड़ा है, इसे चुनौती के रुप में लेते हुए राजस्व लक्ष्यों के अनुसार राशि संग्रहण के लिए समन्वित व ठोस प्रयास करने होंगे। फील्ड अधिकारियों द्वारा राजस्व अर्जन के लिए किये जाने वाले प्रयास परिणाम में परिलक्षित होने चाहिए। श्रीमती अरोरा ने विभागीय मोनेटरिंग व्यवस्था को चाक चोबंद करने और खान निदेशालय स्तर पर राजस्व संग्रहण की नियमित समीक्षा की आवश्यकता प्रतिपादित की। माइनर और मेजर मिनरल ब्लॉकों की ऑक्शन प्रगति की समीक्षा करते हुए मेजर मिनरल के ऑक्शन कैलेण्डर की तरह ही माइनर मिनरल ब्लॉकों के ऑक्शन का भी रोडमैप बनाकर आगामी माहों में नीलामी में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा माइनिंग ब्लॉकों के ऑक्शन से केवल राजस्व संग्रहण ही नहीं होता अपितु वैध खनन को बढ़ावा और अवैध खनन पर भी कारगर रोक हो पाती है। इसके अलावा माइनिंग सेक्टर में निवेश और रोजगार के अवसर विकसित होते हैं। बैठक में राज्य सरकार द्वारा माईनिंग सेक्टर में किये गये ऑटोमाइजेशन की प्रगति, तुलाई कांटों और वीटीएस के ऑटोमाइजेशन का औचक निरीक्षण व अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण पर सख्ती से कार्रवाई की आवश्यकता प्रतिपादित की।

सात बीघा भूमि पर दो अवैध कॉलोनियों को किया ध्वस्त

जयपुर (कासं)। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा कार्रवाई करते हुए जोन-14 में ग्राम भोजदन्ड षिवदासपुरा व पुरूषोत्तमपुरा उर्फ दादिया में करीब 7 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर 02 नवीन अवैध कॉलोनियों को पूर्णत: ध्वस्त किया गया। उप महानिरीक्षक पुलिस श्रीमान् आनन्द शर्मा ने बताया कि जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम भोजदन्ड षिवदासपुरा तह चाकसू जिला जयपुर में करीब 04 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर मिट्टी-ग्रेवल की सड़कें, पत्थरगढी व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-14 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से प्रारिम्भक स्तर पर ही ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। जविप्रा द्वारा ध्वस्तीकरण में हुये व्यय खर्चे की नियमानुसार संबंधित से वसूली की जावेगी। उन्होंने बताया कि जोन-14 के क्षेत्राधिकार में अवस्थित ग्राम पुरूषोत्तमपुरा उर्फ दादिया जिला जयपुर के करीब 03 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति-अनुमोदन के एवं बिना भू रूपान्तरण करवायें भूमि को समतल कर मिट्टी-ग्रेवल की सड़कें व अन्य अवैध निर्माण कर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने की सूचना प्राप्त होने पर आज जोन-14 के राजस्व व तकनीकी स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मषीन व मजदूरों की सहायता से प्रारिम्भक स्तर पर ही ध्वस्त किया जाकर नवीन अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया।

स्वत्वाधिकारी प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक कैलाश त्रिवेदी के लिए उदय प्रिन्टर्स 43-ए, माली कॉलोनी चांदपोल बाहर जयपुर से मुद्रित एवं डी-38, प्रधानपथ, चौमू हाउस, सी स्कीम, जयपुर से प्रकाशित। सम्पादक कैलाश त्रिवेदी* । *पीआईबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार।
फोनः 0141-4038281, Email:- lokjeewanjpr@gmail.com भीलवाड़ा कार्यालयः 207-214, नागौरी गार्डन, लोकजीवन कॉम्पलेक्स, भीलवाड़ा। फोनः 01482-355985, Email:- lokjeewan@gmail.com, मो. 8306792625